



e-ISSN:2582-7219



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 7, Issue 6, June 2024



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.521



6381 907 438



6381 907 438



ijmrset@gmail.com



www.ijmrset.com

मानव अधिकारों का दर्शन: ऐतिहासिक और समकालीन परिप्रेक्ष्य

Shravan Kumar

B.Sc., M.A., Department of Political Science, B.Ed., NET, Pali, Rajasthan, India

सार: मानव अधिकारों के समकालीन सिद्धांत के ऐतिहासिक पूर्ववर्तियों का विश्लेषण आमतौर पर लॉक के योगदान को उच्च स्तर का महत्व देता है। निश्चित रूप से, लॉक ने अधिकारों की नींव पर वैध राजनीतिक प्राधिकार स्थापित करने की मिसाल प्रदान की। यह मानवाधिकारों का निर्विवाद रूप से आवश्यक घटक है।

I. परिचय

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) और उसके बाद की समकालीन मानव अधिकार प्रथाएँ, प्राकृतिक कानून के आधुनिक सिद्धांतों (जैसे ग्रीटियस, पुफेंडोर्फ, लोके) से लेकर मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की प्रसिद्ध फ्रांसीसी घोषणा (1789) तक, पारंपरिक प्राकृतिक अधिकारों के न्यायिक सकारात्मककरण की एक दीर्घकालिक और प्रगतिशील प्रक्रिया का परिणाम हैं। हालाँकि प्राकृतिक अधिकारों के विचार को अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के दौरान किए गए ठोस राजनीतिक संघर्षों में एक निश्चित सफलता मिली थी, लेकिन यह वास्तव में सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ही है कि इस विचार को आरक्षण और यादगार आलोचनात्मक प्रहारों का सामना करना पड़ा है। मैं संक्षेप में कम से कम तीन क्लासिक आलोचनाओं का उल्लेख कर सकता हूँ: ¹ एडमंड बर्क ने मनुष्य के सार्वभौमिक अधिकारों को "अमूर्त सिद्धांत" माना। ² जेरेमी बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को यहाँ तक कि साधारण बकवास करार दिया: ³ अंत में, कार्ल मार्क्स की मनुष्य के अधिकारों की तीखी आलोचना, खास तौर पर अमूर्त (सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ से बाहर) व्यक्तियों के अस्तित्व के प्रति, जो अस्तित्व में होने के तथ्य के आधार पर, प्राकृतिक अधिकार-धारक हैं। ⁴ हाल के समय में भी इस विचार पर महत्वपूर्ण दार्शनिकों द्वारा सैद्धांतिक रूप से सवाल उठाए गए हैं। यह अलास्डेयर मैकइंटायर का मामला है, जिन्होंने उन अधिकारों के अस्तित्व पर सवाल उठाया है जो मनुष्य को केवल मानव होने के कारण प्राप्त हैं, यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे अधिकारों पर विश्वास करना चुड़ैलों और गैंडाओं पर विश्वास करने जैसा है। ⁵

सार्वभौमिक घोषणा जारी होने के बाद, मानवाधिकारों की प्रकृति और नींव के बारे में दार्शनिक बहस मानवाधिकार अभ्यास के साथ उसी गति से विकसित हुई है, इस हद तक कि हाल के दिनों में मानवाधिकारों पर चिंतन को एक वास्तविक नैतिक भाषा का दर्जा दिया गया है। ⁶ मुद्दा यह है कि इस तरह के मूल दस्तावेज़ के व्यावहारिक समझौते ने कई सैद्धांतिक समस्याएँ पैदा कीं। कई बार मानवाधिकारों की कथित सार्वभौमिकता को सैद्धांतिक रूप से अक्षम्य माना जाता है क्योंकि यह जातीय रूप से केंद्रित है और इसलिए राजनीतिक रूप से हानिकारक है। सार्वभौमिक रूप से साझा करने योग्य नींव खोजने की दार्शनिक आवश्यकता और वर्तमान अभ्यास की तत्काल आवश्यकताओं के बीच यह विरोध आजकल मानवाधिकारों के बारे में दार्शनिक सोच के मूल में है। [1,2,3]

विशेष रूप से, जॉन रॉल्स के द लॉ ऑफ पीपल्स (1999) के प्रकाशन ने दर्शन के ऐसे क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया है और वास्तव में, इस बहस में दो विपरीत पक्ष बनाए हैं। एक ओर, हम राजनीतिक सिद्धांतकारों को एक राजनीतिक या व्यावहारिक दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए पाते हैं, जो रॉल्स के दृष्टिकोण से प्रेरित हैं (जो इन अधिकारों की व्याख्या करने की कई कठिनाइयों को छोड़ देता है और उनके सामान्य अर्थ को काफी स्पष्ट मानता है), ⁷ मानते हैं कि मानवाधिकारों को आधुनिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उनके कार्य के प्रकाश में समझा जाना चाहिए, उदाहरण के लिए उन्हें राष्ट्रीय संप्रभुता को सीमित करने वाले अधिकार या हस्तक्षेप के लिए ट्रिगर के रूप में माना जाता है, अर्थात् ऐसे सिद्धांत या नियम जिनके उल्लंघन से अन्य राज्यों द्वारा बाहरी हस्तक्षेप को उचित ठहराया जा सकता है (उदाहरण के लिए, राजनयिक और आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से, या गंभीर मामलों में, सैन्य बल)।

दूसरी ओर, हम रूढ़िवादी या नैतिक विचारों के समर्थकों का एक बहुत ही मिश्रित समूह पाते हैं। ⁸ जेम्स ग्रिफिन और जॉन टैसियोलस जैसे ये दार्शनिक एक सामान्य विचार साझा करते हैं जिसके अनुसार मानवाधिकारों को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाली एकमात्र विशेषता के रूप में मानना, भ्रामक और उचित सैद्धांतिक आधारों की कमी है, यानी मानवीय गरिमा या सभी मनुष्यों की विशेषताओं का विचार। इसलिए, मानवाधिकारों को उनके राजनीतिक कार्यों के आधार पर पहचानने के

बजाय, ये अधिक नैतिक रूप से उन्मुख सिद्धांतकार मानवाधिकारों को उनकी विशिष्ट नैतिक विशेषताओं का हवाला देते हुए परिभाषित करते हैं, जैसे कि वे अधिकार हैं जो मनुष्य को केवल उनकी मानवता के कारण प्राप्त हैं और परिणामस्वरूप, उनकी सार्वभौमिकता है।

इस पेपर के दूसरे पैराग्राफ में मैं रॉल्स की मानवाधिकारों की समझ का पता लगाता हूँ, नींव की समस्या से निपटने के उनके तरीके पर ध्यान केंद्रित करता हूँ और इन अधिकारों की प्रकृति की राजनीतिक अवधारणा के लेखकत्व को उन्हें जिम्मेदार ठहराने की वैधता को चुनौती देता हूँ। तीसरे खंड में मैं दिखाता हूँ कि क्यों अन्य अभ्यास-आधारित खाते (बीटज़ और रेज़) ऐसे अधिकारों के अस्तित्व को सही ठहराने के लिए केवल मानवाधिकार अभ्यास का संदर्भ देने में विफल रहते हैं, और कैसे वे सभी बातों पर विचार करने के बाद, उनके राजनीतिक कार्य को समझाते हैं न कि उनकी प्रकृति को। चौथा खंड नैतिक दृष्टिकोणों और नींव के मामले को संदर्भित करने के उनके तरीके के लिए समर्पित है, जो कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को भी रेखांकित करता है। पाँचवाँ और अंतिम खंड नींव के प्रश्न की व्यावहारिक प्रासंगिकता और न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से, बल्कि अभ्यास के दृष्टिकोण से भी इसे टाला जाना असंभव है। मैं इस विचार के साथ निष्कर्ष निकालता हूँ कि केवल एक नैतिक दृष्टिकोण, नींव पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सैद्धांतिक तत्वों को आधार बनाने के व्यावहारिक महत्व पर ध्यान आकर्षित कर सकता है।

2. मानवाधिकारों की राजनीतिक “प्रकृति” या राजनीतिक “कार्य”? रॉल्स के विवरण की खासियत क्षेत्र के अधिकांश विद्वानों के लिए, रॉल्स मानवाधिकारों की राजनीतिक अवधारणा के जनक हैं, हालांकि रॉल्स का मामला एक विशेष मामला है। सबसे पहले, पीपुल्स का कानून अंतरराष्ट्रीय कानून का ग्रंथ नहीं है, लेकिन, जैसा कि रॉल्स ने स्पष्ट किया है, उन्होंने मानवाधिकारों की अपनी समझ को पीपुल्स के अधिक सामान्य कानून के भीतर विकसित किया है, जिसे “अधिकार और न्याय की एक विशेष राजनीतिक अवधारणा के रूप में माना जाता है जो अंतरराष्ट्रीय कानून और व्यवहार के सिद्धांतों और मानदंडों पर लागू होती है”,⁹ जो सार्वजनिक तर्क की विधि पर निर्भर करता है, जिसमें लोगों के कानून के सिद्धांतों की चयन प्रक्रिया से व्यापक सिद्धांतों से संबंधित तर्कों और विश्वासों को खारिज करना शामिल है, ताकि जातीय रूप से केंद्रित न लगे।¹⁰ ऐसे कानून के सिद्धांत एक सामान्य नैतिक तर्क पर आधारित नहीं हैं, वास्तव में उनके पास एक विशेष प्रकार का औचित्य होना चाहिए, अर्थात् सार्वजनिक तर्क के एक स्वायत्त रूप पर आधारित होना चाहिए। रॉल्स मानवाधिकारों के लिए बहुत कम पृष्ठ और छिटपुट टिप्पणियाँ समर्पित करते हैं क्योंकि, जैसा कि पहले कहा गया है, लोगों का कानून अधिकार और न्याय की एक विशेष राजनीतिक अवधारणा है जो मानवाधिकारों का शुद्ध सिद्धांत होने के बजाय अंतरराष्ट्रीय कानून और व्यवहार के सिद्धांतों और मानदंडों पर लागू होती है। इसलिए, वह जानबूझकर मानवाधिकारों की प्रकृति और नींव के मुद्दे को अनदेखा करते हैं, इन अधिकारों की व्याख्या करने की कई कठिनाइयों को छोड़कर और उनके सामान्य अर्थ और प्रवृत्ति को पर्याप्त रूप से स्पष्ट मानते हैं। इसके अलावा, लोगों का कानून अंतरराष्ट्रीय न्याय का एक सिद्धांत है जिसमें ध्यान का केंद्र लोगों के बीच न्याय है,¹¹ और व्यक्तिगत मनुष्यों के बीच न्याय से संबंधित वैश्विक न्याय का सिद्धांत नहीं है। इस संदर्भ में, मानवाधिकारों की समान लोगों के बीच न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अधिक जटिल खाते के एक तत्व के रूप में संकीर्ण रूप से जांच की जाती है। जैसी स्थिति है, इसे मानवाधिकारों का बहुत अच्छा खाता नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह इस महत्वपूर्ण प्रकार के अधिकारों की प्रकृति और आधारों के लिए जिम्मेदार नहीं है। जैसा कि वे द लॉ ऑफ पीपल्स में दिखाई देते हैं,¹² मानवाधिकारों की जांच नैतिक मूल्यों या आरोपों के रूप में नहीं की जाती है, बल्कि ऐसे साधन के रूप में की जाती है जिसके द्वारा यह मूल्यांकन करने के लिए सार्वजनिक मानदंड हासिल करने का प्रयास किया जाता है कि दूसरे लोग अपने नागरिकों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं और क्या बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जैसा कि वे स्पष्ट करते हैं, “मानवाधिकार लोगों के कानून के लिए आंतरिक हैं और उनका राजनीतिक (नैतिक) प्रभाव होता है, चाहे उन्हें स्थानीय स्तर पर समर्थन मिले या न मिले। यानी, उनका राजनीतिक (नैतिक) बल सभी समाजों तक फैला हुआ है, और वे सभी लोगों और समाजों पर बाध्यकारी हैं, जिनमें गैरकानूनी राज्य भी शामिल हैं। एक गैरकानूनी राज्य जो इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, उसकी निंदा की जानी चाहिए और गंभीर मामलों में उसे बलपूर्वक प्रतिबंधों और यहां तक कि हस्तक्षेप का सामना भी करना पड़ सकता है”।¹³ यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत है कि रॉल्स का उद्देश्य मानवाधिकारों को इस तरह से समझना नहीं है (जिसमें उनकी प्रकृति और आधारों का सिद्धांत शामिल है), बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संतुलन में उनके कार्य की जांच करना है। जब रॉल्स मानवाधिकारों के बारे में बात करते हैं तो वे उनकी प्रकृति का उल्लेख नहीं करते हैं, बल्कि सरकार की आंतरिक संप्रभुता और उसकी सीमाओं की उपयुक्त परिभाषा खोजने के प्रयास के एक हिस्से के रूप में उनकी अंतरराष्ट्रीय भूमिका का उल्लेख करते हैं।¹⁴ फिर भी, इन अधिकारों को समझने के तरीके के बारे में कुछ स्पष्ट संदर्भ हैं: वे राजनीतिक अधिकार नहीं हैं जो नागरिकों के पास एक उचित संवैधानिक लोकतांत्रिक शासन में हैं, बल्कि तत्काल अधिकारों का एक विशेष वर्ग है।¹⁵ साथ ही, वे युद्ध और उसके आचरण के लिए उचित कारणों को प्रतिबंधित करते हैं; वे संवैधानिक अधिकारों, या उदार लोकतांत्रिक नागरिकता के अधिकारों, या अन्य अधिकारों से अलग हैं जो कुछ प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित हैं, दोनों व्यक्तिवादी और संघवादी।¹⁶ उसके बाद, वे कुछ लेकिन स्पष्ट पंक्तियों में लोगों के कानून में मानवाधिकारों के कार्य का वर्णन करते हैं:

मानवाधिकार घरेलू राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं की शालीनता के लिए एक आवश्यक, यद्यपि पर्याप्त नहीं, मानक निर्धारित करते हैं। ऐसा करने में वे लोगों के एक उचित न्यायपूर्ण समाज में अच्छी स्थिति में समाजों के स्वीकार्य घरेलू कानून को सीमित करते हैं। इसलिए मानवाधिकारों के विशेष वर्ग की ये तीन भूमिकाएँ हैं: 1. उनका पालन समाज की राजनीतिक संस्थाओं और उसके कानूनी व्यवस्था की शालीनता की एक आवश्यक शर्त है। 2. उनका पालन अन्य लोगों द्वारा न्यायोचित और बलपूर्वक हस्तक्षेप को बाहर करने के लिए पर्याप्त है, उदाहरण के लिए राजनयिक और आर्थिक प्रतिबंधों द्वारा, या गंभीर मामलों में सैन्य बल द्वारा। 3. वे लोगों के बीच बहुलवाद की सीमा निर्धारित करते हैं।¹⁷

अब तक मैंने जो कुछ कहा है, उसके आधार पर रॉल्लियन सिद्धांत की संरचना में दो अलग-अलग सैद्धांतिक दृष्टिकोणों को पहचाना जा सकता है: [4,5,6]

- मानवाधिकारों को समझने का तरीका: उन्हें सार्वभौमिक के रूप में माना जाना ऐसे अधिकारों के बारे में एक स्पष्ट, यद्यपि सहज और सामान्य ज्ञान पर निर्भर विचार को प्रकट करता है; सार्वजनिक तर्क की विधि के अनुसार, वे किसी भी व्यापक या उदार सिद्धांत पर निर्भर नहीं हैं; वे तत्काल अधिकारों का एक विशेष वर्ग हैं; वे सहयोग की किसी भी प्रणाली के लिए आवश्यक हैं;
- इन अधिकारों को सौंपा गया राजनीतिक कार्य और जिसे आगे दो शाखाओं में स्पष्ट किया जा सकता है: एक ओर, एक राष्ट्रीय क्षेत्र में इस कार्य का महत्व, यानी वह थीसिस जिसके अनुसार कोई भी सरकार अपने राजनीतिक अधिकार के अधीन नागरिकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ बचाव के रूप में संप्रभुता का दावा नहीं कर सकती है, और, अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, राजनीतिक संस्थानों की शालीनता और समाज की कानूनी व्यवस्था की शर्त के रूप में इन अधिकारों का सम्मान; दूसरी ओर, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, उनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व, यानी यह दृष्टिकोण कि ऐसे अधिकारों का सम्मान करना अन्य देशों से किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप (आर्थिक या राजनयिक प्रतिबंध, या सैन्य हस्तक्षेप) को खारिज करने के लिए पर्याप्त शर्त है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को इस महत्व को आरोपित करना प्रश्न को कम आंकने का तरीका नहीं लगता है: रॉल्ल की रुचि लोगों के बीच बातचीत को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का एक सेट खोजने में है, न कि मानव उत्कर्ष और कल्याण के पर्याप्त स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बुनियादी मानवीय अधिकारों में।

इस कारण से, मानवाधिकारों को मुख्य रूप से आंतरिक संप्रभुता की सीमाओं को निर्दिष्ट करने के लिए कार्य करने के रूप में वर्णित किया जाता है।¹⁸ लोगों के कानून के भीतर मानवाधिकारों की भूमिका के कारण,¹⁹ रॉल्ल उन सभी में व्यक्तियों के नैतिक अधिकारों को शामिल नहीं करते हैं।²⁰ रॉल्ल ने मानवाधिकारों के कार्य के बारे में जो लिखा है, उसके अनुसार, उन्हें युद्ध और उसके संचालन को उचित ठहराने वाले कारणों को सीमित करने में व्यावहारिक भूमिका निभाने के रूप में समझा जाना चाहिए, जो सहिष्णुता (अंतरराष्ट्रीय पहलू) के उचित सिद्धांतों से अधिक कुछ नहीं है और एक शासन की आंतरिक स्वायत्तता²¹ (राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य) की सीमाओं को निर्दिष्ट करता है। ये दो पहलू निकटता से संबंधित हैं: यदि कोई शासन मानवाधिकारों का सम्मान करता है, तो उसके राजनीतिक संस्थानों को सभ्य माना जा सकता है और, परिणामस्वरूप, लोगों के समाज में शामिल किया जा सकता है; यदि वह उनकी रक्षा करने में विफल रहता है, या इससे भी बदतर, यह लगातार और व्यवस्थित रूप से उनका उल्लंघन करता है, तो अन्य लोगों द्वारा किया गया बलपूर्वक हस्तक्षेप वैध और उचित माना जाएगा, जिसमें सैन्य बल का उपयोग करने की संभावना भी शामिल है।

एक बार यह निश्चित हो जाने के बाद कि मानवाधिकारों की सूची की संकीर्णता, यद्यपि मानवाधिकारों की संस्कृति के अनुरूप नहीं है, लोगों के कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के लिए उचित ठहराया जा सकता है, ऐसे अधिकारों को समझना कैसे संभव है? क्या उन्हें केवल ऐसे सिद्धांतों के रूप में सोचना वास्तव में उचित है, जिनके उल्लंघन से राज्यों के विरुद्ध बलपूर्वक हस्तक्षेप, यहां तक कि सैन्य हस्तक्षेप भी वैध हो जाता है, जो गैरकानूनी साबित होगा? क्या हम स्वीकार कर सकते हैं कि मानवाधिकारों की प्रकृति केवल उनके राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय कार्य में निहित है? रॉल्ल की मानवाधिकारों के बारे में मुख्य चिंता यह वर्णन करना है कि ऐसे अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रणाली के भीतर कौन सा कार्य करना है)²² और, परिणामस्वरूप, मानवाधिकारों को सार्वभौमिक हितों, क्षमताओं, एजेंसी-आधारित हितों और इसी तरह के संदर्भ में सिद्धांतित नहीं किया जाता है, हालांकि रॉल्ल मानवाधिकारों के अन्य संभावित दृष्टिकोणों से अवगत हैं।²³ लोगों के कानून में मानवाधिकारों का विशेष कार्य राष्ट्रों के बीच संबंधों से संबंधित कुछ राजनीतिक अवधारणाओं को परिभाषित करने के लिए एक आवश्यक तत्व है जैसे कि वैधता, संप्रभुता, एक राज्य से दूसरे राज्य में बाहरी हस्तक्षेप की वैधता आदि। वास्तव में, जैसा कि रॉल्ल ने कुछ अंशों में सुझाया है, मानवाधिकारों का संवर्धन न्यायपूर्ण और सभ्य शासन की विदेश नीति की एक निश्चित सामान्य चिंता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, मानवाधिकारों का संवर्धन अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं में से एक होना चाहिए, शायद सबसे महत्वपूर्ण, जिसे समाज के लोगों को सुधारना होगा।²⁴

निष्कर्ष रूप में, हम कह सकते हैं कि रॉल्ल का प्राथमिक उद्देश्य सार्वभौमिक साझा करने योग्य आधार खोजने के लिए मानव अधिकारों का सिद्धांत तैयार करना नहीं है, बल्कि यह देखते हुए कि उनके ध्यान का केन्द्र ऐसे अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विशेष राजनीतिक भूमिका है, और चूंकि लोगों के बीच संबंधों की स्थिरता उनके सम्मान पर निर्भर करती है, उनका प्रयास विश्वव्यापी साझा

करने योग्य विशिष्ट मानव अधिकारों का एक न्यूनतम सेट स्थापित करना है, और यही उनकी सूची के न्यूनतम होने का मूल कारण होगा।

3. मानवाधिकारों के प्रति राजनीतिक दृष्टिकोण: बुनियाद के सवाल को कैसे दरकिनार किया जाए
मानवाधिकारों के अभ्यास-आधारित विवरण के अधिवक्ताओं के अनुसार, अभ्यास के अधिक कठोर संदर्भ के पक्ष में मूलभूत अपीलों को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि मानवाधिकारों के बारे में सिद्धांत बनाना एक अच्छा जीवन जीने की स्थितियों के सिद्धांत की रूपरेखा तैयार करने जैसा नहीं है।²⁵ यह चार्ल्स बेइटज़ और जोसेफ़ रैज़ का मामला है: हालाँकि वे मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय महत्व और अंतर्राष्ट्रीय चिंता के मामले के रूप में उनके विशेष राजनीतिक मूल्य पर सही ढंग से ज़ोर देते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों में यह कारण नहीं बताया गया है कि मानवाधिकार एक नैतिक आदर्श क्यों है जो राजनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है। जैसा कि बेइटज़ लिखते हैं, "हम अंतर्राष्ट्रीय विमर्श और व्यवहार में मानवाधिकारों की कार्यात्मक भूमिका को बुनियादी मानते हैं: यह शुरू से ही मानव अधिकार की हमारी अवधारणा को बाधित करता है"।²⁶ इसी तरह, रैज़ कहते हैं कि "मानवाधिकार व्यवहार में प्रमुख प्रवृत्ति यह तथ्य लेना है कि एक अधिकार एक मानव अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक अस्वीकार्य पर्याप्त आधार के रूप में इसके विपरीत, मानवाधिकारों की विशेष भूमिका के लिए ही कुछ ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट करे कि वे यह महत्वपूर्ण कार्य क्यों कर सकते हैं। व्यवहार-आधारित विवरणों में जिस चीज को नज़रअंदाज़ किया जाता है, वह है नैतिकता के तत्वों का महत्व, मानव की वे विशेषताएँ जिन्हें मानक सुरक्षा की आवश्यकता होती है।²⁸ साथ ही, ये दार्शनिक मानवाधिकारों की भाषा के [7,8,9] नैतिक आयाम को नकारते प्रतीत होते हैं: यदि व्यक्ति परोपकारिता की नैतिकता से प्रेरित नहीं होते, यदि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव कल्याण की रक्षा करने का नैतिक कर्तव्य महसूस नहीं होता, तो उनके हस्तक्षेप को और क्या प्रेरित करेगा? क्या शायद वे बुनियादी व्यक्तिगत हित (यहां तक कि आर्थिक या राजनीतिक) होंगे जिन्हें बेइटज़ स्वयं हस्तक्षेप को बढ़ावा देने वाले संभावित कारणों के रूप में खारिज करते हैं? ²⁹ क्या वास्तव में मानवाधिकारों का सिद्धांत नैतिक विचारों से स्वतंत्र हो सकता है? वह क्या है जो बताता है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन से ऐसी प्रतिक्रियाएँ क्यों होती हैं जो सामान्य नैतिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उचित नहीं होतीं? उन्हें अनिवार्य रूप से हस्तक्षेप के लिए ट्रिगर माना जाना उनकी प्रकृति को स्पष्ट नहीं कर सकता।³⁰ वास्तव में, मानवाधिकार इसलिए अस्तित्व में नहीं हैं क्योंकि वे कुछ प्रकार के बाहरी हस्तक्षेपों को उचित ठहराते हैं, इसके विपरीत, ऐसे बलपूर्वक कार्य तब उचित ठहराए जाते हैं जब किसी निश्चित मानवाधिकार का उल्लंघन किया जाना माना जाता है। बेइटज़ के विवरण में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मानवाधिकारों को इतना महत्वपूर्ण क्या बनाता है, अर्थात्, मेरा सुझाव है, एक निश्चित व्यक्तिगत नैतिक स्थिति की सुरक्षा, और इसे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, हितों, क्षमताओं, बुनियादी जरूरतों आदि के संदर्भ में समझाया जा सकता है। वह गलत तरीके से यह पता लगाता है कि मानवाधिकार क्या भूमिका निभाते हैं, इस तथ्य को महसूस किए बिना कि यह निर्दिष्ट करना कि किन मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, यह स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है कि ऐसे अधिकारों की अवधारणा कैसे बनाई जानी चाहिए। तदनुसार, मानव गरिमा जैसी अस्पष्ट अवधारणा भी मानवाधिकार विमर्श में केवल एक मुहावरा नहीं है,³¹ बल्कि इसे और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अपने प्रभावशाली राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, जोसेफ़ रैज़ मानवाधिकारों को इस रूप में मानते हैं

अधिकार जो राज्यों की संप्रभुता पर सीमाएं निर्धारित करते हैं, अर्थात् उनका वास्तविक या प्रत्याशित उल्लंघन अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने का एक (अप्राप्य) कारण है, तब भी जब - ऐसे मामलों में जिनमें मानवाधिकारों का उल्लंघन या अपराध का किया जाना शामिल नहीं है - कार्रवाई इस आधार पर अनुमेय या मानक रूप से उपलब्ध नहीं होगी कि इससे राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन होगा।¹³²

रॉल्स के मानवाधिकारों के विचार से प्रेरणा लेते हुए, जो राज्यों की संप्रभुता पर सीमाएँ निर्धारित करने वाले राजनीतिक उपकरण हैं, रैज़ मानवाधिकारों का एक व्यापक हस्तक्षेप खाता विकसित करता है,³³ जिसमें प्रतिबंध और गैर-दबावपूर्ण उपाय भी शामिल हैं। हालाँकि वह स्वीकार करता है कि मानवाधिकार व्यक्तियों द्वारा धारण किए जाने वाले नैतिक अधिकार हैं,³⁴ उनका अस्तित्व विशेष व्यावहारिक स्थितियों पर निर्भर करता है: मानवाधिकारों को संस्थागत मान्यता की आवश्यकता होती है, और व्यक्तियों को वे तभी प्राप्त होते हैं जब सरकार के लिए उन हितों की रक्षा करने के लिए कर्तव्य होने के लिए परिस्थितियाँ उपयुक्त हों जिनकी रक्षा अधिकार करते हैं। इसलिए वे निजी नैतिकता से परे अधिकार हैं,³⁵ क्योंकि केवल संस्थागत पृष्ठभूमि की स्थितियों को ही लोगों को मानवाधिकार प्रदान करने के लिए उपयुक्त कारणों के रूप में स्वीकार किया जाता है।

कुल मिलाकर, अभ्यास-आधारित विवरणों के आगे सबसे महत्वपूर्ण कदम परंपरा के प्राकृतिक अधिकारों के रूप में मानव अधिकारों की भ्रामक अवधारणा पर पुनर्विचार करना है। वास्तव में, राजनीतिक दृष्टिकोण नैतिक या प्राकृतिक अवधारणाओं को अस्वीकार करते हैं, यह तर्क देते हुए कि सार्वभौमिक घोषणा में पृष्ठ किए गए मानव अधिकारों में संस्थागत और राजनीतिक रूपरेखाएँ शामिल हैं, जिन्हें प्राकृतिक अधिकारों के पारंपरिक सिद्धांतों में खोजना असंभव है। यह आलोचना वास्तविक मानवाधिकार अभ्यास के प्रति निष्ठा के नाम पर की जाती है।³⁶ जैसा कि मैं नीचे दिखाऊंगा, यह उन सिद्धांतों को भ्रामक मानकर

अस्वीकार करने का कोई अच्छा कारण नहीं है: उदाहरण के लिए, तसियोलास के रूढ़िवादी सिद्धांत में, मानव अधिकारों के विशिष्ट महत्व और उनके गैर-पश्चिमी मूल्य होने की अन्य दो इच्छाओं के साथ-साथ, मानव अधिकारों के अभ्यास और संस्कृति के प्रति निष्ठा की आवश्यकता शामिल है, जैसा कि 1945 के बाद सामने आया है।³⁷

4. मानव अधिकारों की नैतिक समझ और उनकी बुनियाद पर उनके दृष्टिकोण अधिक सामान्य रूप से, और राजनीतिक अवधारणा के समर्थकों के विपरीत, नैतिक दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले दार्शनिक इस बात पर जोर देते हैं कि नींव के प्रश्न को अधिक सावधानी से संबोधित किया जाना चाहिए, नैतिक तर्क के तत्वों की अपील का आह्वान करते हुए। मैं तसियोलास के नैतिक बहुलवादी विवरण को एक आदर्श उदाहरण के रूप में लेता हूँ: वह मानव सार्वभौमिक हितों और मानव गरिमा के विचार में मानवाधिकारों की नींव की पहचान करता है। पूर्व के संबंध में, वह हितों की एक सूची प्रदान नहीं करता है, बल्कि केवल एक अनिश्चित बुनियादी योजना प्रदान करता है जिसमें ऐसे हितों को वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत, खुले-अंत, बहुलवादी और समग्र के रूप में वर्णित किया जाता है।³⁸ जहाँ तक वह "मानव गरिमा की मानव प्रकृति अवधारणा" को कहते हैं, उनका मतलब है "एक आंतरिक रूप से मूल्यवान् स्थिति जो हमारे सम्मान की हकदार है, एक ऐसी स्थिति जो एक मानव होने के तथ्य पर आधारित है"। यह जानते हुए कि मनुष्य होना क्या है, यह एक अटूट विषय है, वह एक सटीक परिभाषा नहीं देता है, लेकिन कुछ सामान्य तत्वों का सुझाव देता है जो मानव प्रकृति का निर्माण करते हैं, जैसे

मूर्त रूप का एक विशिष्ट रूप; एक निश्चित मोटे परिमाण का एक सीमित जीवनकाल; शारीरिक विकास और प्रजनन की क्षमताएं; मनोवैज्ञानिक क्षमताएं, जैसे कि धारणा, आत्म-चेतना और स्मृति; और, विशेष रूप से तर्कसंगत क्षमताएं, जैसे कि भाषा-उपयोग की क्षमताएं, विभिन्न प्रकार के मानक विचारों (मूल्यांकन संबंधी विचार, विवेकपूर्ण, नैतिक, सौंदर्यपरक और अन्य सहित) को दर्ज करने की क्षमता, और अपने निर्णयों, भावनाओं और कार्यों को उन विचारों के साथ संरेखित करने की क्षमता।³⁹

मानवीय गरिमा के सामान्य विचार और मानवीय हितों की एक खुली सूची पर आधारित यह बहुलवादी विवरण, मानव अधिकारों को किसी विशेष अच्छे की अवधारणा में आधार न बनाने के प्रयास में रेखांकित किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मानवाधिकारों की नींव के अन्य सिद्धांत भी इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात् मानव प्रकृति के विवादास्पद आध्यात्मिक या नैतिक सिद्धांतों का सहारा लिए बिना सभी मनुष्यों की विशिष्ट विशेषताओं में मानवाधिकारों को आधार बनाना। मैं विशेष रूप से मैथ्यू लियाओ के "मौलिक स्थितियों के दृष्टिकोण"⁴⁰ और मास्सिमो रेंजो के "बुनियादी-आवश्यकताओं के दृष्टिकोण"⁴¹ का उल्लेख करता हूँ।

जेम्स ग्रिफिन के एजेंसी (या व्यक्तित्व)-आधारित खाते पर एक अलग मूल्यांकन दिया जाना चाहिए, जो आंतरिक सुसंगति के एक बहुत ही गंभीर मुद्दे से चिह्नित है। उनके विचार में, चूंकि सभी मनुष्यों में वे क्षमताएँ नहीं होतीं जो व्यक्तित्व और एजेंसी की उनकी धारणाओं में निहित हैं, इसलिए^{उन्हें} एक व्यक्ति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। जैसी कि स्थिति है, व्यक्तित्व और एजेंसी मानवाधिकारों के लिए बाध्यकारी सार्वभौमिक आधार नहीं हैं, क्योंकि सभी मनुष्यों के पास ये नहीं होते। व्यक्तित्व और एजेंसी की धारणाएँ व्यापक नहीं हैं और इतनी व्यापक नहीं हैं कि कुछ खास तरह के मनुष्यों (जैसे, नवजात शिशु) को शामिल कर सकें, इसलिए ग्रिफिन का विवरण उस आपत्ति के अधीन है जिसे मैं "गैर-सार्वभौमिक प्रयोज्यता" आपत्ति कहता हूँ: तदनुसार, ग्रिफिन के दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण गलती यह समझने में विफल होना है कि मानवाधिकारों के विचार का तात्पर्य है कि मानवाधिकारों के धारक सभी मनुष्य हैं, उनकी एजेंसी से संबंधित क्षमताओं में किसी भी तरह के अंतर के बिना। जैसा कि जोसेफ रैज़ ने सही ढंग से कहा है, "जब कोई यह कहता है कि शिशुओं या डाउन सिंड्रोम वाले लोगों के पास (कुछ) मानव अधिकार नहीं हैं, तो वह इस विचार को त्याग देता है कि मानव अधिकार हमारी मानवता से उत्पन्न होते हैं"।⁴³

इसके अलावा, सार्वभौमिकता की आवश्यक आवश्यकता की कमी के परिणामस्वरूप, हमें मानवाधिकारों को नैतिक अधिकारों के रूप में मानने के तरीके के बारे में भी अजीब सवाल से निपटना होगा। ग्रिफिन मानवाधिकारों और नैतिक अधिकारों के बीच अंतर करने में विफल रहे, उन्होंने तर्क दिया कि मानवाधिकार नैतिक अधिकारों की व्यापक श्रेणी का केवल एक उचित उप-समूह है।⁴⁴ यह बिंदु तब स्पष्ट हो जाता है जब वह अपने तर्क को भयावह रूप से समाप्त करते हुए दावा करते हैं कि "मानव अधिकारों को शिशुओं, अपरिवर्तनीय कोमा में या उन्नत मनोभ्रंश वाले रोगियों या गंभीर रूप से मानसिक रूप से दोषपूर्ण लोगों तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। और अगर वे उन तक विस्तारित नहीं होते हैं, तो उन्हें भ्रूण तक विस्तारित करने का मामला खोजना मुश्किल है"।⁴⁵ इस आधार पर कि न तो मानव शिशु और भ्रूण, न ही गंभीर रूप से मानसिक रूप से विकलांग और उन्नत मनोभ्रंश से पीड़ित मानक एजेंट हैं, उनके पास सख्ती से कोई मानवाधिकार नहीं है। इसके बजाय, उनके पास "मानव होने के नाते कुछ सामान्य नैतिक अधिकार हो सकते हैं"।^[10,11,12]

इससे पता चलता है कि व्यक्तित्व पर आधारित अधिकार (मानव अधिकार) हैं, और मानवता के विचार पर आधारित अन्य अधिकार (नैतिक अधिकार) हैं। पहले वाले मानक एजेंटों के (मानव) अधिकार हैं और दूसरे वाले मानव (जैसे कि शिशु और मानसिक बीमारी

से प्रभावित व्यक्ति) के पास (नैतिक) अधिकार हैं। हम अवधारणाओं के एक अजीब उलटफेर को देख सकते हैं: प्राणी, निस्संदेह मानव, क्योंकि मानक एजेंसी से संपन्न नहीं हैं, उनके पास कोई मानवाधिकार नहीं है; मानक एजेंट, उन क्षमताओं से संपन्न हैं जो सभी व्यक्तियों के पास नहीं हैं, उनके पास मानवाधिकार हैं, जिनकी मुख्य और अधिक स्पष्ट विशेषता उनकी सार्वभौमिकता है। क्या ये सैद्धांतिक जटिलताएँ मानवाधिकारों के सिद्धांत को एकता, सटीकता और निश्चितता देने के लिए चुकाई जाने वाली कीमत के लायक हैं? वास्तव में, भले ही ग्रिफिन का विवरण निश्चितता में लाभ उठाता है, लेकिन यह सार्वभौमिकता में खो जाता है, वह विशेषता जो "मानव" (और इसलिए सार्वभौमिक) अधिकार के विचार में ही अंकित है। इस तरह, मानवाधिकारों के आधार के रूप में व्यक्तित्व (और एजेंसी) का उनका विवरण एक दुष्क्र, अनसुलझे सट्टा कठिनाइयों की एक श्रृंखला उत्पन्न करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके सिद्धांत का पूरा सैद्धांतिक ढांचा व्यक्ति के संकीर्ण विचार पर आधारित है जो मानव अधिकारों की संस्कृति और नैतिक सामान्य ज्ञान के विपरीत है, और अंतिम रूप से कानून के विपरीत है।

कुल मिलाकर, ये दार्शनिक जिस बात को समझने में सक्षम हैं, या कम से कम जो वे समझते हैं, वह है नींव के प्रश्न का व्यावहारिक असर, सार्वभौमिक मानवाधिकारों के वास्तविक औचित्य और वैश्विक प्रवर्तनीयता और कार्यान्वयन के लिए इसकी अनिवार्यता। मानवाधिकारों की राजनीतिक या व्यावहारिक समझ की सैद्धांतिक वैधता और औचित्य को सत्यापित करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना, यह दिखाना कि यह मानवाधिकार अभ्यास से ही है कि नींव का प्रश्न अनिवार्य रूप से उठता है, मामले के मूल तक पहुँचने के लिए बहुत सही कदम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों का सटीक विश्लेषण पर्याप्त नहीं है: ऐसे लेखकों की स्थिति की मुख्य विशेषताओं को सटीक तरीके से संक्षेप में प्रस्तुत करना, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करना और यह दिखाने का प्रयास करना कि अभ्यास-आधारित विवरण में भी सामान्य नैतिक तर्क के तत्वों और मानवीय गरिमा या बुनियादी जरूरतों जैसे अवधारणाओं और अंतिम मूल्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है, केवल यह निष्कर्ष निकालना कि नैतिक विचारों की अपील से बचना राजनीतिक दृष्टिकोण के रक्षकों की तुलना में अधिक कठिन है।⁴⁸

रूढ़िवादी और नैतिक विचारों के लिए, उनके आवश्यक शब्दों को संक्षेप में प्रस्तुत करना और उनके महत्वपूर्ण तर्कों को इंगित करना, और, जहाँ संभव हो, राजनीतिक अवधारणाओं के साथ आंशिक संगतता, एक ऐसा चरण है जिसे पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन यह पर्याप्त कदम नहीं है। नैतिक सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक मानव अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में समझना है, और यही कारण है कि कई विद्वान ऐसे सिद्धांतों को अस्वीकार करते हैं: उदाहरण के लिए, बेट्टज़, दार्शनिक हठधर्मिता के आरोप लगाते हैं कि वे सिद्धांत मानव अधिकारों को अनैतिहासिक और सार्वभौमिक प्राकृतिक अधिकारों के रूप में व्याख्या करते हैं, यहाँ तक कि लौकिक अर्थ में भी, क्योंकि ऐसे विवरण प्रासंगिक नहीं होंगे क्योंकि उनका मानव अधिकारों के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है।⁴⁹ इसलिए, अनुसंधान के इस क्षेत्र की मुख्य प्रतिबद्धता मूल प्राकृतिक सिद्धांतों को संशोधित करने का तरीका खोजना है, मानव अधिकारों में कालातीत प्राकृतिक अधिकारों को नहीं बल्कि ऐतिहासिक अधिकारों को स्वीकार करना, जो मानव जाति के सांस्कृतिक विकास द्वारा आकार लेते हैं, जिनकी सामग्री लगातार बदल रही है, उनके सार्वभौमिक नैतिक आयाम को नकारे बिना। इस कारण से, तसियोलास ने शक्तिशाली अभिव्यक्ति "ऐतिहासिक रूप से विवश सार्वभौमिकता" गढ़ी है, जिसका अर्थ है कि "मानव अधिकार मनुष्य के रूप में मनुष्यों के पास होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि इतिहास में हर समय और हर समाज में हों। इसके बजाय, वे कुछ निश्चित व्यापक रूप से परिभाषित ऐतिहासिक संदर्भों में सभी के पास होंगे"।⁵⁰ सार्वभौमिकता के एक अस्थायी रूप से विवश रूप का ऐसा विचार, जो एक आदर्शवादी प्राकृतिक कानून दृष्टिकोण को खारिज करता है, यह सुझाव देता है कि कौन से मानवाधिकार मौजूद हैं, इस सवाल का जवाब केवल कुछ निर्दिष्ट ऐतिहासिक संदर्भों के भीतर ही दिया जा सकता है। जैसा कि तसियोलास लिखते हैं, "आज और निकट भविष्य के लोगों के लिए, मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो मानव होने और एक सामाजिक दुनिया में रहने के कारण प्राप्त होते हैं जो आधुनिकता की शर्तों के अधीन है"।⁵¹

कुछ उदाहरण देने के लिए, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के अधिकार जैसे मानवाधिकार निस्संदेह एक निश्चित राजनीतिक और संस्थागत पृष्ठभूमि के अस्तित्व को पूर्व निर्धारित करते हैं, हालांकि उत्तरार्द्ध उनके विशिष्ट नैतिक चरित्र को नहीं हटाता है जो सभी व्यक्तियों की मानवीय गरिमा और समान नैतिक स्थिति के विचार से आता है। लोगों को शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि स्थापित शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियाँ मौजूद हैं, बल्कि उनके पास ऐसे अधिकार हैं क्योंकि वे एक सार्थक मानव जीवन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। यदि ये अधिकार इतने मौलिक हैं, तो ये अधिकार उन संस्थानों को स्थापित करने के अच्छे कारण हो सकते हैं जो उनकी रक्षा करते हैं।⁵² तदनुसार, नैतिक समझ के समर्थकों ने मानवाधिकारों के अपने विचार को "प्राकृतिक" अधिकारों के रूप में इस अर्थ में आकार दिया है कि वे अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों के पास केवल उनकी (प्राकृतिक) मानवता के गुण के कारण और राजनीतिक संस्थाओं के बावजूद हैं, हालांकि इस बात से इनकार करना असंभव है कि राजनीतिक संस्थाएँ उनके प्रवर्तन के लिए मौलिक हैं। इस अर्थ में, मानवाधिकार कुछ मौलिक नैतिक मूल्यों के बीच की खाई को पाटते हैं जो उनकी नींव के रूप में काम कर सकते हैं और संस्थागत और सामाजिक व्यवस्थाएँ जिन्हें उन्हें लागू करना चाहिए।⁵³ इस तरह, नैतिक सिद्धांत व्यवहार के प्रति निष्ठा की बाध्यता को पूरा करने में विफल नहीं होते हैं, क्योंकि वे मानवाधिकारों को एक निश्चित प्रकार के सामाजिक और संस्थागत संदर्भ से अनिवार्य रूप से जुड़े हुए मानते हैं। संस्थागत पृष्ठभूमि में निहित होने से मानवाधिकारों के अधिकार, उनके

आवश्यक नैतिक आयाम, या सभी मनुष्यों की सामान्य मानवता, गरिमा और समानता के उनके ऑन्टोलॉजिकल आधारों से समझौता नहीं होता है।

5. दर्शन के लिए मानवाधिकार की आवश्यकता क्यों: नींव के सैद्धांतिक प्रश्न का व्यावहारिक महत्व में जिस सामान्य थीसिस का समर्थन करना चाहता हूँ, वह यह है कि मानवाधिकारों की नींव के प्रश्न का व्यवहार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिणाम है। बेशक, हालाँकि सार्वभौमिक घोषणा का मसौदा तैयार करते समय नींव की सैद्धांतिक समस्या को टाला जा सकता था, लेकिन जब मानवाधिकारों को वास्तव में विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाना होता है, तो विभिन्न अंतर्निहित नैतिक या राजनीतिक विचार उभर कर सामने आते हैं। वास्तव में, यदि मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता उनकी प्रकृति का हिस्सा है, तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा समर्थित नैतिक सिद्धांतों की एक बड़ी विविधता है। तदनुसार, नींव का सैद्धांतिक मुद्दा मानव गरिमा की अवधारणा की पहचान करने के लिए आवश्यक हो जाता है जिसका हम बचाव करना चाहते हैं। इसलिए, मानवाधिकारों की ऐतिहासिक सामग्री मानव गरिमा के उस विचार पर निर्भर करती है जिससे हम उनका अनुमान लगाते हैं या उन्हें आधार बनाते हैं।

आम तौर पर, मानवाधिकारों के राजनीतिक सिद्धांतों का उपयोग नींव की समस्या के व्यावहारिक परिणामों को कम आंकने के लिए किया जाता है। यहां तक कि नॉरबर्टो बॉबियो ने भी मौजूदा बहस का अनुमान लगाते हुए तर्क दिया कि "यह जानने का मामला नहीं है कि कौन से और कितने अधिकार हैं, उनकी प्रकृति क्या है और वे किस आधार पर आधारित हैं, क्या वे प्राकृतिक या ऐतिहासिक, निरपेक्ष या सापेक्ष हैं; यह अधिकारों की गारंटी देने और उनके निरंतर उल्लंघन को रोकने का सबसे सुरक्षित तरीका खोजने का सवाल है"।⁵⁴ बॉबियो के अनुसार, मानवाधिकारों की मूल समस्या उनके औचित्य की आवश्यकता में नहीं है, बल्कि उन्हें संरक्षित करने में है। मूलभूत तर्क, जैसे कि ये अधिकार क्या हैं, हमारे पास ये क्यों हैं और वे किस पर आधारित हैं, को पूरी तरह से टाला जाना चाहिए, इस बात को समझने के पक्ष में कि ये अधिकार वास्तव में अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संदर्भ में क्या भूमिका निभाते हैं, सिर्फ इसलिए कि यह एक दार्शनिक समस्या नहीं है, बल्कि राजनीतिक है। नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोणों के बीच बहस में, नींव की समस्या की व्यावहारिक प्रासंगिकता ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक ओर इसे अप्रासंगिक माना जाता है, दूसरी ओर मानव अधिकारों को उचित ठहराने के तरीके के बारे में बुनियादी सवालों के जवाब देने के लिए अधिक शक्तिशाली तर्क प्रदान करने के रूप में अनुशंसित किया जाता है।

हालाँकि हाल के अध्ययनों में हम दोनों प्रतिमानों की पूरक प्रकृति को दिखाने के कई प्रयास पा सकते हैं,⁵⁵ मुझे लगता है कि वर्तमान शोध में कम खोजा गया मार्ग राजनीतिक अवधारणा की एक अलग समझ का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य यह दिखाना है कि वास्तव में मानवाधिकारों का यह विवरण संवैधानिक रूप से अपर्याप्त है और उनकी आवश्यक प्रकृति को समझने की आवश्यकता के संबंध में अपर्याप्त है। तासियोलास के अलावा, मुझे ऐसा लगता है कि केवल [13,14,15] कुछ अन्य लेखकों ने राजनीतिक दृष्टिकोण की संरचनात्मक अपर्याप्तता की समस्या को संबोधित किया है, दो प्रतिमानों को समेटने का विरोध किया है और राजनीतिक दृष्टिकोण को इसके उद्देश्य के विरुद्ध, सामान्य नैतिक तर्क के कुछ तत्वों की अपील करने का आरोप लगाया है। इसे ही रेन्जो "राजनीतिक पर नैतिकता की प्राथमिकता" कहते हैं।⁵⁶ तदनुसार, अभ्यास-आधारित सिद्धांतों के रक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे नैतिक तत्वों के महत्व के अपने सिद्धांतगत इनकार को उचित ठहराएँ, भले ही वे उन पर बार-बार आएँ। राजनीतिक अवधारणा की विशेषता वाली बुनियादी सैद्धांतिक विफलता पर जोर देते हुए, हम देख सकते हैं कि यह, सभी बातों पर विचार करने पर, मानवाधिकारों द्वारा निभाई जाने वाली राजनीतिक भूमिका का केवल एक सिद्धांत प्रदान करता है, जो गलत तरीके से नींव के प्रश्न को उठाता है। परिणामस्वरूप, केवल अभ्यास पर जोर देने वाला एक अभ्यास-आधारित विवरण, सैद्धांतिक मुद्दों का सामना करने से बचता है, जिनका अभ्यास पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है, सबसे ऊपर सांस्कृतिक विविधता और मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता के बीच संबंध की समस्या। इसलिए, एक संभावित समाधान एक सिद्धांत विकसित करने में नहीं है जो दो प्रतिमानों को समेटता है, बल्कि यह दिखाने में है कि मानवाधिकारों के सिद्धांत को न केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में उनके राजनीतिक कार्य का उचित विन्यास शामिल करना चाहिए, बल्कि उनकी प्रकृति और नींव का भी विवरण होना चाहिए क्योंकि उत्तरार्द्ध अभ्यास के लिए प्रासंगिक हैं। दूसरे शब्दों में, मानवाधिकारों के सिद्धांत को उनके कार्यान्वयन के व्यावहारिक पहलू और उनके औचित्य के सैद्धांतिक पहलू को ध्यान में रखना चाहिए।

जैसा कि चीजें हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की भ्रांति सिद्धांत की अपूर्णता में नहीं है, बल्कि इस बात की जागरूकता की कमी में है कि नींव की समस्या का व्यावहारिक प्रभाव होता है: यदि यह सच है कि सार्वभौमिक घोषणा के समय नींव के प्रश्न को अलग रखा गया था क्योंकि इससे निस्संदेह असंगत विभाजन और संघर्ष उत्पन्न होते, तो यह भी सच है कि जब मानवाधिकारों को विशेष मामलों में व्यावहारिक रूप से लागू किया जाना है, तो नींव का प्रश्न अपरिहार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, लोकतंत्रीकरण के प्रश्न पर विचार करें: लोकतंत्र के वैश्वीकरण की प्रवृत्ति को आज की दुनिया की सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता के साथ कैसे जोड़ा जाए जो मानवाधिकारों के समकालीन अभ्यास की विशेषता है? क्या वास्तव में लोकतंत्र के लिए एक मानव अधिकार मौजूद है (जैसा कि

सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 21 में कहा गया है) या क्या हमें यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि ऐसा अधिकार सार्वभौमिक है, जैसा कि बेइटज़ और कोहेन जैसे राजनीतिक अवधारणा के सिद्धांतकारों द्वारा दावा किया गया है? ⁵⁸ इस मामले में, यह कहना होगा कि अभ्यास-आधारित दृष्टिकोण स्वयं अभ्यास के साथ असंगत है। फिर राजनीतिक अवधारणा द्वारा अपील किए जाने वाले मानवाधिकारों के अभ्यास को सांस्कृतिक विविधता के मुद्दे के साथ कैसे जोड़ा जाए? यहाँ हमें नींव के प्रश्न पर लौटने की स्पष्ट आवश्यकता महसूस होती है क्योंकि मानवाधिकारों की समकालीन संस्कृति द्वारा अपनाए जाने वाले संकीर्णतावाद या पश्चिमी शैली के कथित सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के आरोप, ऐसी समस्याएँ उत्पन्न करते हैं जिनका समाधान सबसे पहले सैद्धांतिक रूप से खोजा जाना चाहिए, जो हमें मानवीय गरिमा, मानवीय विकास और कल्याण के विचार पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, वे सभी तत्व जिन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण कम करके आँकता है, उनकी व्यावहारिक प्रासंगिकता को अस्वीकार करता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता हमें इस विचार पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करती है, जो कि राज द्वारा सुझाए गए विचार के विपरीत है, कि किसी निश्चित मानवाधिकार का अस्तित्व आकस्मिक कारकों (सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक-संस्थागत) से संबंधित है, या मान्यता के लिए अनुकूल परिस्थितियों और इसके कार्यान्वयन और प्रवर्तनीयता के लिए उपयुक्त रणनीति से संबंधित है। ⁵⁹ इसलिए, हालाँकि मानवाधिकार निस्संदेह एक सांस्कृतिक तथ्य है, एक प्रकार का सामाजिक अभ्यास है जिसमें उनका संस्थागत आयाम में निहित होना शामिल है, फिर भी वे अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को केवल मानव जाति से संबंधित होने के कारण प्राप्त हैं। और भले ही यह नकारा नहीं जा सकता कि राजनीतिक संस्थाओं की वैधता का आकलन करने में मानवाधिकारों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ⁶⁰ राजनीतिक वैधता के आकलन के लिए नैतिक मानदंड के रूप में उनकी भूमिका के आधार पर उनकी वास्तविक प्रकृति की व्याख्या नहीं की जा सकती। वास्तव में, जैसा कि टैसियोलस ने सुझाया है, जब हम मानवाधिकारों के बारे में बात करते हैं तो जो दांव पर होता है वह केवल कानूनी-संस्थागत या राजनीतिक आयाम नहीं होता है, बल्कि एक वास्तविक मानवाधिकार लोकाचार होता है जो हमें व्यक्तिगत रूप से और सीधे चुनौती देता है। ⁶¹ यदि सार्वभौमिक मानवाधिकारों के बारे में बात करना समझ में आता है, तो यह इन अधिकारों के अस्तित्व के कारण है, जो केवल मानव के अस्तित्व के तथ्य के लिए है, जो इस प्रकार न केवल अधिकारों के विषय हैं, बल्कि तीसरे पक्ष के लिए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के स्रोत भी हैं, जो संस्थाएं या व्यक्ति हो सकते हैं। वास्तव में, यह तथ्य कि संस्थाएं, जैसे कि राज्य, सबसे उपयुक्त और उचित कर्तव्य-धारक हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मानवाधिकारों को व्यक्तियों के बीच नैतिकता के तत्वों के रूप में भी नहीं माना जा सकता है।

इन अधिकारों की सार्वभौमिकता किसी तरह इस अर्थ में सहज है कि यह मानवाधिकारों की अवधारणा में ही निहित है कि उन्हें सार्वभौमिक माना जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए। उनकी सार्वभौमिकता पर सवाल उठाने का मतलब इस अवधारणा के मूल अर्थ पर सवाल उठाना होगा: यदि उन अधिकारों को सार्वभौमिक के रूप में डिज़ाइन नहीं किया गया था, तो हम उन्हें मानवाधिकार क्यों कहेंगे? वे मानवाधिकार (सार्वभौमिक) हैं क्योंकि वे किसी व्यक्ति में निहित हैं, चाहे किसी सार्वजनिक शक्ति या राजनीतिक संस्था की मान्यता या विशेषता कुछ भी हो। इस अर्थ में, समकालीन शोध को यह दिखाने के लिए उन्मुख होना चाहिए कि नैतिक अवधारणा मानवाधिकारों की रक्षा की तात्कालिकता को बेहतर ढंग से कैसे व्याख्या करती है, क्योंकि यह उन्हें एक कोड या कानूनी सिद्धांतों की प्रणाली के रूप में नहीं, बल्कि एक "विशिष्ट नैतिक संवेदनशीलता" के तत्वों के रूप में समझती है, ⁶² जो हमें उन्हें सबसे पहले हमारे जीवन में व्याप्त एक नैतिक प्रतिमान के हिस्से के रूप में विचार करने की अनुमति देता है, जो सार्वजनिक और निजी, समाज और राज्य के बीच की सीमाओं को मिटा देता है, बिना संस्थागत और राजनीतिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता को नकारे जिस पर लागू होने के लिए भरोसा किया जा सके। साथ ही, यह अवधारणा उन्हें संस्थागत बनाने की आवश्यकता पर जोर देती है, जो आखिरकार, केवल एक और तथ्य है। ⁶³ इस प्रकार, उन्हें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सार्वभौमिक नैतिक मांगों के रूप में माना जाता है, न कि केवल कानूनी उपकरणों के रूप में, ⁶⁴ यह विभिन्न संदर्भों में विभिन्न नैतिक एजेंटों के लिए मानक निहितार्थों को प्रकाश में लाने का प्रयास करने के लिए उपयोगी और शक्तिशाली होगा, ⁶⁵ यह उजागर करते हुए कि मानवाधिकारों की अंतरराष्ट्रीय राजनीति के व्यावहारिक पहलुओं के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने से अंततः उनकी प्रकृति का एक विकृत दृष्टिकोण मिलेगा। मानवाधिकार कानून में अच्छी तरह से परिलक्षित हो सकते हैं, कानून को प्रेरित कर सकते हैं, और कई परिस्थितियों में, ऐसे आदर्शों के रूप में काम कर सकते हैं जिन पर विधायी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, ये हमेशा आगे के तथ्य होते हैं जो उनकी संरचनात्मक विशेषताओं को परिभाषित नहीं करते हैं। मानवाधिकारों को मुख्य रूप से "सामाजिक नैतिकता में प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति" के रूप में देखा जाना चाहिए, ⁶⁶ और इस तरह उन्हें आधिकारिक अनादर को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। ⁶⁷

इसके अतिरिक्त, मानवाधिकारों के अभ्यास में स्थिरता और निष्ठा की आवश्यकता के कारण, जो सार्वभौमिक घोषणा से उत्पन्न होती है, इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि बाद की प्रस्तावना में पहले से ही मानवाधिकारों की एक अंतर्निहित समझ पाई जाती है जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति से परे है, और यह व्यक्तियों के बीच संबंधों की नैतिकता का भी पूर्वाभास कराती है, जिसके अनुसार मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा के रूप में माना जाना चाहिए।

सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए उपलब्धि का एक सामान्य मानक, जिसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग, इस घोषणा को निरंतर ध्यान में रखते हुए, शिक्षण और शिक्षा के माध्यम से इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा और प्रगतिशील राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपायों के माध्यम से, सदस्य राज्यों के लोगों के बीच और उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लोगों के बीच, उनकी सार्वभौमिक और प्रभावी मान्यता और पालन सुनिश्चित करेगा।¹

यह बिलकुल स्पष्ट है कि, यदि सार्वभौमिक घोषणा का कार्य मानवाधिकारों के सम्मान को मान्यता देना और बढ़ावा देना है, तो ऐसे अधिकार पहले से ही विद्यमान हैं और कानून के परिणाम नहीं हैं। इसलिए, वे अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को उनकी मानवता के कारण ही प्राप्त हैं। इस ढांचे में, मानवीय गरिमा की अवधारणा को सर्वोच्च नैतिक मूल्य के रूप में माना जाता है, जिसकी रक्षा करना सांस्कृतिक और संस्थागत उपकरणों के रूप में मानवाधिकारों का कर्तव्य है। इसके अलावा, मैरिटेन की इस प्रसिद्ध टिप्पणी कि केवल इस शर्त पर व्यावहारिक समझौते की संभावना है कि "कोई हमसे क्यों नहीं पूछेगा"⁶⁹ को एक निश्चित मूल्यांकन नहीं माना जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे एक बार और हमेशा के लिए स्थापित एक वाचा की उपलब्धि, क्योंकि ऐसा व्यावहारिक समझौता, एक ऐसा लक्ष्य होने से बहुत दूर है जिसके आगे जाना उचित नहीं है, बल्कि एक प्रारंभिक बिंदु है जिससे नींव के बारे में एक प्रश्न उठता है।⁷⁰ वास्तव में, एक व्यावहारिक समझौता केवल मानवाधिकारों के अस्तित्व को उचित नहीं ठहराता है, और हम नींव के बारे में केवल इसलिए शोध करते हैं क्योंकि घोषणाएँ और अंतर्राष्ट्रीय वाचाएँ अपर्याप्त हैं। इस दृष्टिकोण से, एक व्यावहारिक समझौता अंतिम समाधान के बजाय एक सैद्धांतिक समस्या बनी हुई है।

जैसा कि अमर्त्य सेन ने कहा है, "इस विचार में कुछ बहुत ही आकर्षक बात है कि दुनिया में कहीं भी हर व्यक्ति के पास, नागरिकता या क्षेत्रीय कानून के बावजूद, कुछ बुनियादी अधिकार हैं, जिनका दूसरों को सम्मान करना चाहिए",⁷¹ और मानवाधिकारों के सिद्धांत का मूल उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि यह कैसे संभव है, कथित सार्वभौमिक मानवाधिकारों और नैतिक या सांस्कृतिक बहुलवाद के बीच तनाव के दीर्घकालिक प्रश्न का सामना करना।⁷² किसी भी अन्य मुद्दे की तरह, मानवाधिकारों के मामले में भी दर्शन उन कारणों पर प्रकाश डालता है कि किसी समस्या का समाधान खोजना क्यों कठिन है, हालांकि यह हमें कोई निश्चित उत्तर नहीं देता है।

इस क्षेत्र में दर्शन का कार्य यह स्पष्ट करना है कि नैतिक तर्क और नैतिकता किस प्रकार सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाट सकती है। मेरा सुझाव है कि इस मार्ग को अपनाने में, मानवाधिकारों के प्रति नैतिक दृष्टिकोण में उन आधारभूत तत्वों के व्यावहारिक महत्व को इंगित करने की क्षमता है जिनसे हम मानवाधिकारों का अनुमान लगाते हैं, जिससे हम केवल व्यवहार पर आधारित सिद्धांतों को निश्चित रूप से खारिज कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि सिद्धांत और व्यवहार दोनों में मानवाधिकार विमर्श का भविष्य उन कारणों के ज्ञान से जुड़ा है जो उन्हें उचित ठहराते हैं और, कम से कम सिद्धांत रूप में, यह इस अर्थ में है कि मानवाधिकारों को आधार देने का सैद्धांतिक प्रयास उनके वास्तविक संरक्षण को भी मजबूत करता है। मानवाधिकारों के दर्शन को मानवाधिकारों को आधार देने के लिए साक्ष्य और तेजी से सम्मोहक तर्कों की तलाश करनी होगी, ताकि मानवाधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं द्वारा दिए गए बचाव को उन्हें उचित ठहराने के लिए दिए गए कारणों से कमजोर बनाया जा सके।

मैंने मानवाधिकारों की नींव के सवाल के महत्व पर जोर देने की कोशिश की, जो कि उनकी व्यावहारिक प्रासंगिकता के संबंध में है, यह दिखाते हुए कि कैसे यह केवल एक सैद्धांतिक मुद्दा प्रतीत होता है, व्यवहार से ही व्यावहारिक निहितार्थ उत्पन्न होते हैं। नैतिक सिद्धांतकारों और राजनीतिक अवधारणाओं के अधिवक्ताओं के बीच मानवाधिकारों की प्रकृति पर समकालीन बहस में, उत्तरार्द्ध नींव के सवाल को नजरअंदाज कर रहे हैं, वास्तव में मानवाधिकार अभ्यास के संदर्भ द्वारा दी गई आश्वस्त निश्चितता के पक्ष में सैद्धांतिक मुद्दों से निपटने से डरते हैं, साथ ही एक तरह के आधारभूत तत्व के रूप में भी। विशेष रूप से, राजनीतिक दृष्टिकोण के सिद्धांतकार नींव के सवाल को व्यवहार के लिए अप्रासंगिक मानते हैं, क्योंकि इसे वैचारिक संघर्षों का एक खतरनाक क्षेत्र माना जाता है, जिसे मानवाधिकारों के बारे में अधिक जरूरी व्यावहारिक समझौते, एक वास्तविक आम सहमति तक पहुंचने के लिए टाला जाना चाहिए। नैतिक सिद्धांतों के लिए, उन्हें अधिक प्रभावशाली के रूप में अनुशंसित किया जाना चाहिए क्योंकि वे उन मूल्यों के व्यावहारिक महत्व को कम करके आंके बिना संस्थागत या राजनीतिक पृष्ठभूमि के महत्व को स्वीकार करते हैं जिन्हें वे मानवाधिकारों के आधारभूत तत्व के लिए मौलिक मानते हैं। दरअसल, वे व्यवहार-आधारित सिद्धांतों पर यह आरोप लगाते हैं कि वे सामान्य नैतिक तर्क के तत्वों को कोई उपयुक्त महत्व नहीं देते हैं, जो अंततः अपरिहार्य हैं जब हम मानवाधिकारों और उनके औचित्य के बारे में बात करते हैं।

II. विचार-विमर्श

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के कई सिद्धांतों की जड़ें प्राचीन समाजों और धर्मों में हैं।

कन्फ्यूशियस विचारधारा प्राचीन चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं पर आधारित है। कन्फ्यूशियस विश्वास में, समाज में व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और उन्हें सभी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। परिवार में धार्मिकता का एक मजबूत स्तर होता है और व्यक्तियों को सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए योगदान देने के लिए बाध्य किया जाता है। [16,17,18]

मो त्जु ने कन्फ्यूशियस के विचारों को आगे बढ़ाते हुए यह प्रस्ताव रखा कि समाज में न्याय मानवीय तरीके से किया जाना चाहिए ताकि सभी लोगों के हितों की पूर्ति हो सके।

इसी प्रकार का दृष्टिकोण इस्लाम में भी पाया जाता है, जहां लोगों पर अल्लाह, एक-दूसरे के लिए प्रावधान करने तथा खुशहाली विकसित करने का दायित्व है।

इसी प्रकार, बौद्ध शिक्षाएं दुख को समाप्त करने के साधन के रूप में करुणा के मूल्य को बढ़ावा देती हैं, तथा वर्तमान क्षण के साथ-साथ अगले जीवन में मानव अधिकारों पर भी ध्यान केंद्रित करती हैं।

प्राचीन शासकों जैसे मेनेस, हम्मुराबी, ड्रेको, सोलन और मनु से जुड़ी संहिताएँ उनके समाजों के लिए आचरण के मानकों को रेखांकित करती हैं, जो सीमित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रों में मौजूद थीं। इनमें से कुछ संहिताओं की व्याख्या मानवाधिकारों की स्वीकृति के रूप में की गई है।

1200-300 ईसा पूर्व में, प्राचीन इस्राएलियों के धर्मग्रंथों ने ईसाई और मुस्लिम सोच का आधार बनाया। दस आज्ञाएँ जीवन और दूसरों की संपत्ति के प्रति सम्मान की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं। यह सिद्धांत कि कोई व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि उसे दोषी साबित न कर दिया जाए और शरण देने की परंपरा यहूदी कानून से उत्पन्न हुई है।

40-100 ई. में ईसाई धर्म में ईश्वर के समक्ष समानता की शिक्षा दी जाती थी। अनुयायियों से आग्रह किया जाता था कि वे भूखे को खाना खिलाएँ, नंगे को कपड़े पहनाएँ और अपने दुश्मनों को माफ़ कर दें।

ग्रीक और रोमन साम्राज्यों ने स्वतंत्र पुरुष नागरिकों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिये थे।

इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि मानवाधिकारों की उत्पत्ति कई अलग-अलग समाजों में हुई है। उनका विकास नैतिक और धार्मिक संहिताओं और कानूनी ढाँचों के माध्यम से हुआ है।

III. परिणाम

मानवाधिकार, वे अधिकार जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को केवल मानव होने के कारण, या अंतर्निहित मानवीय भेद्यता के परिणामस्वरूप, या क्योंकि वे न्यायपूर्ण समाज की संभावना के लिए आवश्यक हैं, प्राप्त होते हैं। चाहे उनका सैद्धांतिक औचित्य कुछ भी हो, मानवाधिकार उन मूल्यों या क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है जो मानव एजेंसी को बढ़ाने या मानव हितों की रक्षा करने के लिए सोचा जाता है और चरित्र में सार्वभौमिक घोषित किया जाता है, किसी अर्थ में सभी मनुष्यों, वर्तमान और भविष्य के लिए समान रूप से दावा किया जाता है।

यह एक आम धारणा है कि हर जगह मनुष्य को अपने व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विविध मूल्यों या क्षमताओं की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। यह भी एक आम धारणा है कि यह आवश्यकता - चाहे नैतिक या कानूनी मांग के रूप में कल्पना की गई हो या व्यक्त की गई हो - अक्सर सामाजिक और प्राकृतिक शक्तियों द्वारा दर्दनाक रूप से निराश की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप शोषण, उत्पीड़न, उत्पीड़न और अन्य प्रकार के अभाव होते हैं। इन जुड़वां टिप्पणियों में आज "मानव अधिकार" और उनसे जुड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं की शुरुआत गहराई से निहित है।

ऐतिहासिक विकास

मानवाधिकार शब्द अपेक्षाकृत नया है और यह केवल द्वितीय विश्व युद्ध, 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाते के बाद से ही रोजमर्रा की बोलचाल में आया है। इसने प्राकृतिक अधिकार वाक्यांश की जगह ली, जो 19वीं शताब्दी में आंशिक रूप से अप्रचलित हो गया क्योंकि प्राकृतिक कानून की अवधारणा (जिससे यह घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था) कानूनी प्रत्यक्षवाद के उदय के साथ विवादास्पद हो गई थी। कानूनी प्रत्यक्षवाद ने रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा लंबे समय से समर्थित सिद्धांत को खारिज कर दिया कि कानून होने के लिए कानून का नैतिक होना जरूरी है। मानवाधिकार शब्द ने बाद के वाक्यांश मनुष्य के अधिकारों को भी प्रतिस्थापित किया,

प्राचीन ग्रीस और रोम में उत्पत्ति

मानवाधिकार के अधिकांश छात्र मानवाधिकार की अवधारणा की उत्पत्ति को इस प्रकार मानते हैं: प्राचीन ग्रीस और रोम, जहां यह ईसाई धर्म के सिद्धांतों से निकटता से जुड़ा हुआ था। स्टोइक, जो मानते थे कि मानव आचरण का मूल्यांकन प्रकृति के नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए और उसके साथ सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण सोफोकल्स [19,20,21] के नाटक एंटीगोन में दिया गया है, जिसमें शीर्षक चरित्र, राजा क्रैओन द्वारा अपने मारे गए भाई को दफनाने के आदेश की अवहेलना करने के लिए फटकार लगाए जाने पर, दावा करता है कि उसने देवताओं के अपरिवर्तनीय कानूनों के अनुसार काम किया।

आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि स्टोइकवाद ने इसके गठन और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसी तरह रोमन कानून ने प्राकृतिक कानून के अस्तित्व की अनुमति दी और इसके साथ-साथ जूस जेंटियम ("राष्ट्रों का कानून") के अनुसार- कुछ सार्वभौमिक अधिकार जो नागरिकता के अधिकारों से परे थे। रोमन न्यायविद के अनुसार उदाहरण के लिए, उलपियन के अनुसार, प्राकृतिक कानून वह है जो प्रकृति द्वारा, न कि राज्य द्वारा, सभी मनुष्यों को सुनिश्चित किया जाता है, चाहे वे रोमन नागरिक हों या नहीं।

हालांकि, मध्य युग के बाद ही प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अधिकारों से जुड़ पाया। ग्रीको-रोमन और मध्यकालीन समय में, प्राकृतिक कानून के सिद्धांत मुख्य रूप से "मनुष्य" के अधिकारों के बजाय कर्तव्यों से संबंधित थे। इसके अलावा, जैसा कि अरस्तू और सेंट थॉमस एक्विनास के लेखन में स्पष्ट है, इन सिद्धांतों ने दासता और दासता की वैधता को मान्यता दी और ऐसा करने में, शायद मानवाधिकारों के सबसे महत्वपूर्ण विचारों को बाहर रखा जैसा कि आज समझा जाता है - स्वतंत्रता (या स्वतंत्रता) और समानता। ब्रिटानिका प्रीमियम सदस्यता प्राप्त करें और अनन्य सामग्री तक पहुंच प्राप्त करें। अब सदस्यता लें

मानव अधिकारों की अवधारणा प्राकृतिक अधिकारों के रूप में (दायित्व के शास्त्रीय प्राकृतिक क्रम के विपरीत) कुछ बुनियादी सामाजिक परिवर्तनों द्वारा संभव हुई, जो 13वीं शताब्दी के आसपास यूरोपीय सामंतवाद के पतन के साथ धीरे-धीरे शुरू हुई और पुनर्जागरण के माध्यम से वेस्टफेलिया की शांति (1648) तक जारी रही। इस अवधि के दौरान, धार्मिक असहिष्णुता और राजनीतिक और आर्थिक बंधन का प्रतिरोध; प्राकृतिक कानून के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में शासकों की स्पष्ट विफलता; और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और सांसारिक अनुभव के लिए अभूतपूर्व प्रतिबद्धता जो कि समाज की विशेषता थी। पुनर्जागरण ने मिलकर प्राकृतिक कानून की अवधारणा को कर्तव्यों से अधिकारों में बदल दिया। यूरोपीय महाद्वीप पर एक्विनास और ह्यूगो ग्रेटियस की शिक्षाएँ, मैग्ना कार्टा (1215) और उसके साथी चार्टर ऑफ़ द फॉरेस्ट्स (1217), पेटिशन ऑफ़ राइट (1628), और इंग्लैंड में इंग्लिश बिल ऑफ़ राइट्स (1689) इस बदलाव के संकेत थे। प्रत्येक ने तेजी से लोकप्रिय हो रहे इस दृष्टिकोण की गवाही दी कि मनुष्य को कुछ शाश्वत और अविभाज्य अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें कभी भी त्यागा नहीं गया जब मानव जाति ने प्राकृतिक व्यवस्था से सामाजिक व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए "संकुचित" किया और "राजाओं के दैवी अधिकार" के दावे से कभी भी कम नहीं हुए। प्राकृतिक कानून को प्राकृतिक अधिकारों में परिवर्तित किया गया



जॉन लोके

जॉन लोके, कैनवास पर तैलचित्र, हरमन वेरेलस्ट द्वारा, 1689; नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी, लंदन में। (अधिक)

प्राकृतिक अधिकारों के अर्थ या निहितार्थ के रूप में प्राकृतिक कानून की आधुनिक अवधारणा को मुख्य रूप से 17वीं और 18वीं शताब्दी के विचारकों द्वारा विस्तृत किया गया था। 17वीं शताब्दी की बौद्धिक-और विशेष रूप से वैज्ञानिक-उपलब्धियाँ (हॉब्स का भौतिकवाद, डेसकार्टेस और लीबनिज़ का तर्कवाद, स्पिनोज़ा का सर्वेश्वरवाद और बेकन और लियोपोल्डो का अनुभववाद सहित) लोके ने प्राकृतिक कानून और सार्वभौमिक व्यवस्था में एक विशिष्ट आधुनिक विश्वास को प्रोत्साहित किया और 18वीं शताब्दी के दौरान - तथाकथित नैतिकता का युगमानवीय तर्क और मानवीय मामलों की पूर्णता में बढ़ते विश्वास से प्रेरित ज्ञानोदय ने इस विश्वास की अधिक व्यापक अभिव्यक्ति को जन्म दिया। लॉक के लेखन विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे, जो यकीनन आधुनिक समय के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक-कानून सिद्धांतकार थे, और 18वीं सदी के विचारकों के कार्य जिन्हें 'द ग्रेटेस्ट नेचुरल लॉ' के नाम से जाना जाता है। दार्शनिक, जो मुख्य रूप से पेरिस में केंद्रित थे, में मोटेस्क्यू, वोल्तेयर और जीन-जैक्स रूसो शामिल थे। लॉक ने विस्तार से तर्क दिया, मुख्य रूप से अंग्रेजी गौरवशाली क्रांति (1688-89) से जुड़े लेखों में, कि कुछ अधिकार स्पष्ट रूप से मनुष्यों के रूप में व्यक्तियों से संबंधित हैं (क्योंकि ये अधिकार मानव जाति के नागरिक समाज में प्रवेश करने से पहले काल्पनिक "प्रकृति की स्थिति" में मौजूद थे); उनमें से प्रमुख जीवन, स्वतंत्रता (मनमाने शासन से मुक्ति) और संपत्ति के अधिकार हैं; नागरिक समाज में प्रवेश करने पर, मानव जाति ने राज्य को आत्मसमर्पण कर दिया - एक "सामाजिक अनुबंध" के अनुसार - केवल इन प्राकृतिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार और स्वयं अधिकार नहीं; और इन अधिकारों को सुरक्षित करने में राज्य की विफलता जिम्मेदार, लोकप्रिय क्रांति के अधिकार को जन्म देती है। दार्शनिकों ने, लॉक और अन्य लोगों के आधार पर और कारण में एक समान सर्वोच्च विश्वास के साथ विचार की कई और विविध धाराओं को अपनाया उन्होंने प्रकृति, मानवता और समाज को नियंत्रित करने वाले सार्वभौमिक रूप से मान्य सिद्धांतों की खोज करने और उन पर कार्य करने का प्रयास किया, जिसमें अविभाज्य "मानव अधिकार" भी शामिल थे, जिन्हें वे एक मौलिक नैतिक और सामाजिक सिद्धांत मानते थे।

आश्चर्य की बात नहीं है कि इस उदार बौद्धिक उथल-पुथल ने 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में पश्चिमी दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला। इंग्लैंड में शानदार क्रांति और उसके परिणामस्वरूप अधिकारों के विधेयक के साथ, इसने क्रांतिकारी आंदोलन की लहर के लिए तर्क प्रदान किया जिसने पश्चिम को झकझोर दिया, खासकर उत्तरी अमेरिका और फ्रांस में। थॉमस जेफरसन, जिन्होंने लोके और मोटेस्क्यू का अध्ययन किया था, ने 17वीं शताब्दी के सादे गद्य को काव्यात्मक वाक्पटुता प्रदान की। 14 जुलाई 1776 को 13 अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा घोषित स्वतंत्रता की घोषणा:

हम इन सत्यों को स्वयंसिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं, कि उन्हें उनके रचयिता द्वारा कुछ अविभाज्य अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज शामिल हैं। इसी प्रकार, मार्किंस डी लाफायेत, जिन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन की घनिष्ठ मित्रता प्राप्त की और जिन्होंने अमेरिकी क्रांति की कठिनाइयों को साझा किया, ने अंग्रेजी और अमेरिकी क्रांतियों की घोषणाओं की नकल की। 26 अगस्त, 1789 को मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा, जिसमें कहा गया कि "मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान अधिकारों के साथ रहते हैं" और "प्रत्येक राजनीतिक संघ का उद्देश्य मनुष्य के प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकारों का संरक्षण है।" संक्षेप में, प्राकृतिक अधिकारों के विचार ने, जो मानवाधिकारों की समकालीन धारणा का पूर्ववर्ती है, 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में राजनीतिक निरंकुशता के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्तव में, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों का सम्मान करने में शासकों की विफलता ही इस विकास के लिए जिम्मेदार थी।

"बकवास": प्राकृतिक अधिकारों के आलोचक

हालाँकि, प्राकृतिक अधिकारों का विचार इसके आलोचकों से रहित नहीं था। सबसे पहले, क्योंकि यह अक्सर धार्मिक रूढ़िवाद से जुड़ा हुआ था, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दार्शनिक और राजनीतिक उदारवादियों के लिए कम आकर्षक हो गया। इसके अतिरिक्त, क्योंकि वे अनिवार्य रूप से निरंकुश शब्दों में परिकल्पित थे, प्राकृतिक अधिकारों को तेजी से एक दूसरे के साथ संघर्ष करने वाला माना जाने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर दाएं और बाएं दोनों तरफ से शक्तिशाली दार्शनिक और राजनीतिक हमले हुए।

उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में, रूढ़िवादी राजनीतिक विचारक जैसे एडमंड बर्क और डेविड ह्यूम जैसे उदारवादियों के साथ एकजुट हुए जेरेमी बेंथम ने इस सिद्धांत की निंदा की, पहला डर था कि प्राकृतिक अधिकारों की सार्वजनिक पुष्टि सामाजिक उथल-पुथल का कारण बनेगी, दूसरा इस चिंता से कि कहीं प्राकृतिक अधिकारों की घोषणाएं और उद्घोषणाएं प्रभावी कानून का विकल्प न बन जाएं। फ्रांस में क्रांति पर अपने विचार (1790) में, बर्क - जो प्राकृतिक कानून में विश्वास करते थे, जिन्होंने फिर भी इस बात से इनकार किया कि इससे "मनुष्य के अधिकार" प्राप्त किए जा सकते हैं - ने मानव समानता की "राक्षसी कल्पना" की घोषणा करने के लिए मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के मसौदा तैयार करने वालों की आलोचना [22,23,24] की, जो, उनके तर्क के अनुसार, "श्रमपूर्ण जीवन के अस्पष्ट मार्ग पर यात्रा करने वाले पुरुषों में झूठे विचारों और व्यर्थ उम्मीदों को प्रेरित करने" का काम करता है। उपयोगितावाद के संस्थापकों में से एक बेंथम भी कम तिरस्कारपूर्ण नहीं थे। "अधिकार," उन्होंने लिखा,

कानून की संतान है; वास्तविक कानून से वास्तविक अधिकार आते हैं; लेकिन काल्पनिक कानूनों से, "प्रकृति के कानून" से, काल्पनिक अधिकार आते हैं।... प्राकृतिक अधिकार सरासर बकवास है; प्राकृतिक और अप्रतिबंधित अधिकार (एक अमेरिकी वाक्यांश)... बयानबाजी वाली बकवास है, बेकार की बकवास है।

बेन्थम से सहमति जताते हुए ह्यूम ने जोर देकर कहा कि प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार अवास्तविक आध्यात्मिक घटनाएं हैं।

प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों पर यह हमला 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तीव्र और व्यापक हो गया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के अपने जोरदार बचाव के बावजूद घोषणा की कि अधिकार अंततः उपयोगिता पर आधारित हैं। जर्मन न्यायविद फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविग्री, इंग्लैंड के सर हेनरी मेन और अन्य "इतिहासवादी" कानूनी विचारकों ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकार विशेष समुदायों के लिए अद्वितीय सांस्कृतिक और पर्यावरणीय चर का एक कार्य है। अंग्रेजी न्यायविद जॉन ऑस्टिन ने तर्क दिया कि एकमात्र कानून "संप्रभु का आदेश" (हॉब्स का एक वाक्यांश) है। और 20वीं सदी की शुरुआत के तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने जोर देकर कहा कि एकमात्र सत्य वह है जिसे सत्यापन योग्य अनुभव द्वारा स्थापित किया जा सकता है और इसलिए नैतिक घोषणाएँ संज्ञानात्मक रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं। प्रथम विश्व युद्ध तक शायद ही कोई सिद्धांतकार था जो प्राकृतिक कानून की तर्ज पर "मनुष्य के अधिकारों" की रक्षा करता। वास्तव में, 19वीं सदी के जर्मन के प्रभाव में आदर्शवाद और उभरते यूरोपीय राष्ट्रवाद की समानांतर अभिव्यक्तियाँ, कुछ थे-उदाहरण के लिए, मार्क्सवादी, हालांकि व्यक्तिगत अधिकारों को पूरी तरह से खारिज नहीं करते थे, लेकिन उनका मानना था कि अधिकार, चाहे वे किसी भी स्रोत से प्राप्त हों, मुख्य रूप से समुदायों या पूरे समाज और राष्ट्रों के होते हैं।

धारणा की दृढ़ता

हालाँकि प्राकृतिक अधिकारों का उत्कर्ष काल छोटा साबित हुआ, फिर भी अधिकारों का विचार कायम रहा। गुलामी का उन्मूलन, कारखाना कानून का कार्यान्वयन, लोकप्रिय शिक्षा और ट्रेड यूनियनवाद का उदय, सार्वभौमिक मताधिकार आंदोलन - ये और 19वीं सदी के सुधारवादी आवेगों के अन्य उदाहरण इस बात के पर्याप्त प्रमाण देते हैं कि इस विचार को समाप्त नहीं किया जाना था, भले ही इसकी पूर्व-कल्पना सामान्य संदेह का विषय बन गई हो। लेकिन यह तब तक नहीं था जब तक कि यह उत्थान और पतन नहीं हुआ। नाजी जर्मनी ने बताया कि मानवाधिकारों का विचार वास्तव में अपने आप में आया। नाजी शासन द्वारा किए गए कई भयानक अत्याचारों को नाजी कानूनों और आदेशों द्वारा आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था, और इस तथ्य ने कई लोगों को आश्चर्य किया कि कानून और नैतिकता किसी भी विशुद्ध आदर्शवादी या उपयोगितावादी या अन्य परिणामवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं हो सकते। इस दृष्टिकोण के अनुसार, कुछ कार्य बिल्कुल गलत हैं, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों; मनुष्य कम से कम साधारण सम्मान के हकदार हैं।

आज अधिकांश कानूनी विद्वान और दार्शनिक - विशेष रूप से उदार पश्चिम में - इस बात पर सहमत हैं कि प्रत्येक मनुष्य के पास, कम से कम सिद्धांत रूप में, कुछ बुनियादी अधिकार हैं। वास्तव में, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय चिंता के कुछ अनिवार्य रूप से अलग-थलग प्रदर्शनों को छोड़कर, 20वीं सदी के अंतिम आधे हिस्से को मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय और सार्वभौमिक मान्यता के जन्म का प्रतीक कहा जा सकता है। चार्टर की स्थापना उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र में सभी सदस्य देशों ने "जाति, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी के लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए सार्वभौमिक सम्मान और पालन" की प्राप्ति के लिए संयुक्त और अलग-अलग कार्रवाई करने का संकल्प लिया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में, कई संस्कृतियों के प्रतिनिधियों ने इसमें निर्धारित अधिकारों का समर्थन किया "सभी लोगों और सभी देशों के लिए उपलब्धि के एक सामान्य मानक के रूप में।" और 1976 में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICESCR) और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICCPR), जिनमें से प्रत्येक को 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया, लागू और प्रभावी हुई। सार्वभौमिक घोषणा और उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल के साथ, इन दस्तावेजों को अंततः "मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक" के मूल तत्वों के रूप में जाना जाने लगा।

मानव अधिकारों को परिभाषित करना

यह कहना कि मानवाधिकारों के सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिल गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे अधिकारों की प्रकृति और दायरे या वास्तव में उनकी परिभाषा के बारे में पूरी सहमति है। बुनियादी सवालों में से जिनके अभी तक निर्णायक जवाब नहीं मिले हैं, वे निम्नलिखित हैं: क्या मानवाधिकारों को दैवीय, नैतिक या कानूनी अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए; क्या उन्हें अंतर्ज्ञान, संस्कृति, रीति-रिवाज, सामाजिक अनुबंध, वितरण न्याय के सिद्धांतों या खुशी या मानवीय गरिमा की प्राप्ति के लिए पूर्वापेक्षाओं के रूप में मान्य किया जाना चाहिए; क्या उन्हें अपरिवर्तनीय या आंशिक रूप से प्रतिसंहरणीय के रूप में समझा जाना चाहिए; और क्या वे संख्या और विषय-वस्तु में व्यापक या सीमित होने चाहिए। यहां तक कि जब मानवाधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है, तब भी विवाद होते हैं: क्या मानवाधिकार सामान्य हितों पर संकीर्ण रूप से कल्पित विशेष हितों को

प्राथमिकता देने का एक तरीका है; क्या वे मुख्य रूप से प्रगतिशील अभिजात वर्ग के राजनीतिक उपकरण हैं; क्या वे पश्चिमी आर्थिक साम्राज्यवाद के लिए एक शिकार हैं; और इसी तरह। इस प्रकार कभी-कभी यह दावा किया जाता है कि मानवाधिकारों के बारे में कोई सार्वभौमिक रूप से सहमत सिद्धांत या समझ मौजूद नहीं है।

मानव अधिकारों की प्रकृति: सामान्यतः स्वीकृत मान्यताएँ

इस आम सहमति की कमी के बावजूद, व्यापक रूप से स्वीकृत (और परस्पर संबंधित) कई धारणाएँ मानवाधिकारों को परिभाषित करने के कार्य में सहायता कर सकती हैं। इनमें से पाँच विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, हालाँकि ये भी विवाद से अछूते नहीं हैं। सबसे पहले, उनके अंतिम उद्गम या औचित्य की परवाह किए बिना, मानवाधिकारों को राजनीतिक शक्ति, धन, ज्ञान और अन्य पोषित मूल्यों या क्षमताओं के लिए व्यक्तिगत और समूह दोनों मांगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए समझा जाता है, जिनमें से सबसे मौलिक सम्मान और इसके सभी अन्य ऐसे मूल्यों या क्षमताओं की खोज में पारस्परिक सहिष्णुता और आपसी सहनशीलता के घटक तत्व हैं। नतीजतन, मानवाधिकारों में इन मूल्यों या क्षमताओं और कानूनों और परंपराओं की वैधता का न्याय करने के मानकों की प्राप्ति में बाधा डालने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ दावे दोनों शामिल हैं। सबसे नीचे, मानवाधिकार राज्य की संप्रभुता और शक्ति को योग्य बनाते हैं, कभी-कभी पूर्व को सीमित करते हुए भी उत्तराद्ध का विस्तार करते हैं [25,26,27] (जैसा कि कुछ आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के मामले में, उदाहरण के लिए)। तेजी से, मानवाधिकारों को "निजी संप्रभुता" को भी योग्य बनाने के लिए कहा जाता है

दूसरा, मानवाधिकारों को आमतौर पर कुछ अस्पष्ट अर्थों में "मौलिक" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो "गैर-ज़रूरी" दावों या "वस्तुओं" से अलग है। वास्तव में, कुछ सिद्धांतकार मानवाधिकारों को एक या दो मुख्य अधिकारों तक सीमित करने की हद तक चले जाते हैं - उदाहरण के लिए, जीवन का अधिकार या समान अवसर का अधिकार। प्रवृत्ति "बुनियादी ज़रूरतों" पर ज़ोर देने और "मात्र इच्छाओं" को खारिज करने की है।

तीसरा, अलग-अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों, अलग-अलग विश्वदृष्टिकोणों और विभिन्न मूल्य या क्षमता प्रणालियों के भीतर और उनके बीच अपरिहार्य अंतर-निर्भरता को दर्शाते हुए, मानवाधिकार दावों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है, जो सबसे न्यायोचित (या लागू करने योग्य) से लेकर सबसे अधिक आकांक्षात्मक तक है। मानवाधिकार कानूनी और नैतिक दोनों आदेशों का हिस्सा होते हैं, कभी-कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। वे मानवीय मामलों में "है" और "चाहिए" दोनों को अभिव्यक्त करते हैं।

चौथा, मानवाधिकारों के अधिकांश दावे - हालाँकि यकीनन सभी नहीं (गुलामी, नरसंहार या यातना से मुक्ति उल्लेखनीय अपवाद हैं) - इस सीमा से योग्य हैं कि विशेष उदाहरणों में व्यक्तियों या समूहों के अधिकारों को उतना ही प्रतिबंधित किया जाता है जितना कि दूसरों के तुलनीय अधिकारों और समग्र सामान्य हित को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। इस सीमा को देखते हुए, जो अधिकारों को कर्तव्यों से जोड़ता है, मानवाधिकारों को कभी-कभी "प्रथम दृष्टया अधिकार" नामित किया जाता है, ताकि आम तौर पर उनके बारे में निरंकुश शब्दों में सोचना या बात करना बहुत कम या कोई मतलब नहीं रखता।

अंत में, यदि किसी अधिकार को मानव अधिकार माना जाता है, तो इसे अनिवार्य रूप से सामान्य या सार्वभौमिक चरित्र माना जाता है, किसी अर्थ में यह सभी मनुष्यों के पास हर जगह समान रूप से होता है, जिसमें कुछ मामलों में अजन्मे बच्चे भी शामिल हैं। राजाओं के दैवी अधिकार और विशेषाधिकार की अन्य ऐसी अवधारणाओं के विपरीत, मानवाधिकार सिद्धांत रूप में पृथ्वी पर हर व्यक्ति तक विस्तारित होते हैं, योग्यता या आवश्यकता की परवाह किए बिना, केवल मानव होने के कारण या क्योंकि वे अंतर्निहित मानवीय भेद्यता को कम करते हैं या सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक हैं।

हालाँकि, कई महत्वपूर्ण मामलों में, ये सभी धारणाएँ उत्तर देने की तुलना में अधिक प्रश्न उठाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि, जैसा कि तेजी से कहा जा रहा है, मानवाधिकार निजी शक्ति को योग्य बनाते हैं, तो वे ऐसा कब और कैसे करते हैं? यह कहने का क्या मतलब है कि कोई अधिकार मौलिक है, और किस महत्व या तात्कालिकता के मानकों के अनुसार इसका मूल्यांकन किया जाता है? मानवाधिकारों के न्यायशास्त्र के हिस्से के रूप में कानूनी अधिकारों से अलग नैतिक अधिकारों को अपनाने का क्या मूल्य है? क्या गैर-न्यायसंगत अधिकार बयानबाजी से अधिक महत्व रखते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? कब और किस मानदंड के अनुसार एक व्यक्ति या लोगों के समूह का अधिकार दूसरे के अधिकार को रास्ता देता है? क्या होता है जब व्यक्तिगत और समूह के अधिकार टकराते हैं? सार्वभौमिक मानवाधिकार कैसे निर्धारित किए जाते हैं? क्या वे संस्कृति या विचारधारा का कार्य हैं, या वे योग्यता या मूल्य की किसी अंतरराष्ट्रीय सहमति के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं? यदि उत्तराद्ध है, तो क्या प्रश्न में आम सहमति क्षेत्रीय या वैश्विक है? वास्तव में ऐसी आम सहमति कैसे सुनिश्चित की जाएगी, और इसे राष्ट्रों और लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ कैसे जोड़ा जाएगा? क्या सार्वभौमिक मानवाधिकारों का अस्तित्व राष्ट्रीय संप्रभुता की धारणा के साथ असंगत है? क्या सुपरनैशनल मानदंडों, संस्थानों और प्रक्रियाओं में मृत्युदंड, बच्चों की शारीरिक सज़ा, "ऑनर किलिंग", घूँघट पहनना, महिला जननांग काटना, पुरुष खतना, हथियार रखने का दावा किया गया अधिकार और अन्य प्रथाओं पर स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कानूनों को निष्प्रभावी करने की शक्ति होनी चाहिए? मानवाधिकार बहस में कुछ लोगों के लिए, यह इस बारे में एक और विवाद खड़ा करता है कि ऐसी स्थितियाँ लोकतंत्र और प्रतिनिधि सरकार की पश्चिमी अवधारणाओं के साथ कैसे मेल खाती हैं।

दूसरे शब्दों में, हालांकि सटीक, उपरोक्त पाँचों धारणाएँ मानवाधिकारों की विषय-वस्तु और वैध दायरे तथा उनमें मौजूद प्राथमिकताओं, यदि कोई हों, के बारे में सवालों से भरी हैं। मानवाधिकारों की उत्पत्ति और औचित्य के मुद्दे की तरह, ये सभी पाँच विवादास्पद हैं।

मानवाधिकारों की विषय-वस्तु: अधिकारों की तीन “पीढ़ियाँ”

सभी मानक परंपराओं की तरह, मानवाधिकार परंपरा भी अपने समय की उपज है। इसलिए, मानवाधिकारों की विषय-वस्तु और वैध दायरे तथा उनके बीच दावा की गई प्राथमिकताओं पर बहस को बेहतर ढंग से समझने के लिए, आधुनिक समय की शुरुआत से ही मानवाधिकार परंपरा को प्रभावित करने वाले प्रमुख विचारधाराओं और कार्य-प्रणालियों पर ध्यान देना उपयोगी है।

इस संबंध में फ्रांसीसी न्यायविद द्वारा प्रस्तुत मानव अधिकारों की तीन “पीढ़ियों” की धारणा विशेष रूप से सहायक है। फ्रांसीसी क्रांति के तीन विषयों से प्रेरित होकर, वे हैं: पहली पीढ़ी, जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों (लिबर्टी) से बनी है; आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की दूसरी पीढ़ी (égalité); और एकजुटता या समूह अधिकारों की तीसरी पीढ़ी (fraternité)। वासक का मॉडल, ज़ाहिर है, एक अत्यंत जटिल ऐतिहासिक रिकॉर्ड की सरलीकृत अभिव्यक्ति है, और इसका उद्देश्य एक रैखिक प्रक्रिया का सुझाव देना नहीं है, जिसमें प्रत्येक पीढ़ी अगली को जन्म देती है और फिर मर जाती है। न ही इसका मतलब यह है कि एक पीढ़ी दूसरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, या यह कि पीढ़ियाँ (और उनके अधिकारों की श्रेणियाँ) अंततः पृथक हैं। तीन पीढ़ियों को संचयी, अतिव्यापी और, इस बात पर ज़ोर देना महत्वपूर्ण है, अन्योन्याश्रित और एक दूसरे से जुड़ी हुई समझा जाता है।

लिबर्टे : नागरिक और राजनीतिक अधिकार

पहली पीढ़ी, नागरिक और राजनीतिक अधिकार मुख्यतः ऊपर उल्लिखित 17वीं और 18वीं सदी के सुधारवादी सिद्धांतों (यानी अंग्रेजी, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों से जुड़े सिद्धांतों) से प्राप्त हुए हैं। उदार व्यक्तिवाद के राजनीतिक दर्शन और अहस्तक्षेप के संबंधित आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत से प्रभावित होकर, पहली पीढ़ी मानवाधिकारों को सकारात्मक (“अधिकार”) की तुलना में नकारात्मक शब्दों (“से स्वतंत्रता”) में अधिक समझती है; यह मानवीय सम्मान की खोज में सरकार के हस्तक्षेप की तुलना में परहेज का पक्षधर है। इस प्रकार, इस पहली पीढ़ी में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 2-21 में निर्धारित अधिकार शामिल हैं, जिनमें लिंग, नस्लीय और समकक्ष प्रकार के भेदभाव से स्वतंत्रता शामिल है; व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार; गुलामी या अनैच्छिक दासता से स्वतंत्रता; यातना और क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या सजा से स्वतंत्रता उत्पीड़न से बचने का अधिकार; विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता; राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; शांतिपूर्ण सभा और संघ की स्वतंत्रता; और सरकार में सीधे या स्वतंत्र चुनावों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार। इसमें संपत्ति रखने का अधिकार और मनमाने ढंग से उससे वंचित न किए जाने का अधिकार भी शामिल है - वे अधिकार जो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों और पूंजीवाद के उदय में लड़े गए हितों के लिए मौलिक थे [28,29,30]

फिर भी यह कहना गलत होगा कि ये और अन्य प्रथम पीढ़ी के अधिकार पूरी तरह से “सकारात्मक” अधिकारों के विपरीत “नकारात्मक” के विचार से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार, निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार, उत्पीड़न से बचने के लिए शरण का अधिकार, या स्वतंत्र चुनाव का अधिकार, स्पष्ट रूप से कुछ सकारात्मक सरकारी कार्रवाई के बिना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इस प्रथम पीढ़ी की अवधारणा में जो स्थिर है वह है स्वतंत्रता की अवधारणा, एक ऐसा कवच जो व्यक्ति को - अकेले और दूसरों के साथ मिलकर - राजनीतिक अधिकार के दुरुपयोग से बचाता है। यह मूल मूल्य है। दुनिया के लगभग हर देश के संविधान में शामिल और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अपनाई गई अधिकांश अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं और वाचाओं पर हावी (बड़े पैमाने पर नाजी युग के दौरान नागरिक संबद्धता और लोकतांत्रिक समावेश के मूल सिद्धांतों के क्रूर इनकार के कारण), मानवाधिकारों की इस अनिवार्य रूप से पश्चिमी उदार अवधारणा को कभी-कभी राज्य के हेगेल के महिमामंडन पर हॉब्स और लॉक के व्यक्तिवाद की जीत के रूप में रोमांटिक किया जाता है।

Égalité : आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार

दूसरी पीढ़ी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार मुख्यतः समाजवादी काल में उत्पन्न हुए। परंपरा, जिसकी 19वीं सदी के आरंभ में फ्रांस में सेंट-सिमोनियन आंदोलन के अनुयायियों के बीच पूर्वाभास हुआ था और तब से हुए क्रांतिकारी संघर्षों और कल्याणकारी आंदोलनों द्वारा इसे विभिन्न रूप से बढ़ावा दिया गया। बड़े हिस्से में, यह पूंजीवादी विकास के दुरुपयोग और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अंतर्निहित और अनिवार्य रूप से गैर-आलोचनात्मक अवधारणा की प्रतिक्रिया है, जिसने श्रमिक वर्गों और औपनिवेशिक लोगों के शोषण को बर्दाश्त किया और यहां तक कि उसे वैध भी बनाया। ऐतिहासिक रूप से, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पहली पीढ़ी के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के विपरीत हैं, और इन्हें नकारात्मक शब्दों (“से स्वतंत्रता”) की तुलना में सकारात्मक शब्दों (“अधिकार”) में अधिक माना जाता है; इनमें शामिल मूल्यों या क्षमताओं के समान उत्पादन और वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के परहेज की तुलना में हस्तक्षेप की अधिक आवश्यकता होती है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 22-27 में निर्धारित कुछ अधिकार उदाहरणार्थ हैं, स्वयं और परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार; शिक्षा का अधिकार; तथा अपने वैज्ञानिक, साहित्यिक और कलात्मक उत्पादन की सुरक्षा का अधिकार।

लेकिन जिस तरह पहली पीढ़ी (नागरिक और राजनीतिक अधिकार) द्वारा अपनाए गए सभी अधिकारों को “नकारात्मक अधिकार” के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है, उसी तरह दूसरी पीढ़ी (आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार) द्वारा अपनाए गए

सभी अधिकारों को "सकारात्मक अधिकार" के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, रोजगार की स्वतंत्र पसंद का अधिकार, ट्रेड यूनियन बनाने और उसमें शामिल होने का अधिकार, और समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार (अनुच्छेद 23 और 27) को आनंद सुनिश्चित करने के लिए स्वाभाविक रूप से सकारात्मक राज्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, दूसरी पीढ़ी के अधिकांश अधिकारों के लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे वितरणात्मक न्याय के कुछ मानदंडों के अनुसार अमूर्त वस्तुओं की तुलना में भौतिक वस्तुओं की अधिक मांगों को शामिल करते हैं। दूसरी पीढ़ी के अधिकार, मौलिक रूप से, सामाजिक समानता के दावे हैं। हालांकि, आंशिक रूप से अंतरराष्ट्रीय मामलों में समाजवादी-साम्यवादी और संगत "तीसरी दुनिया" के प्रभाव के तुलनात्मक रूप से देर से आने के कारण, लेकिन हाल ही में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से लेसेज-फेयर पूंजीवाद के उदय और नवउदारवादी, मुक्त-बाज़ार अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के कारण, इन "समानता अधिकारों" का अंतरराष्ट्रीयकरण अपेक्षाकृत धीमी गति से हो रहा है और निकट भविष्य में इसके पूरी तरह से परिपक्व होने की संभावना नहीं है। दूसरी ओर, जैसे-जैसे समय के साथ अनियमित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पूंजीवाद द्वारा बनाई गई सामाजिक असमानताएँ अधिक से अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं और लिंग या नस्ल के आधार पर स्पष्टीकरण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं हैं, यह संभावना है कि दूसरी पीढ़ी के अधिकारों की माँग बढ़ेगी और परिपक्व होगी, और कुछ मामलों में हिंसा को भी बढ़ावा मिलेगा। वास्तव में, यह प्रवृत्ति 2010 के दशक की शुरुआत में ही स्पष्ट हो गई थी, विशेष रूप से यूरोप में मितव्ययिता उपायों के खिलाफ व्यापक विरोधों में, जब यूरो-जोन ऋण संकट सामने आया और व्यापक प्रयासों में (जिसमें "ऑक्यूपाई" आंदोलन जैसे सामाजिक आंदोलन भी शामिल थे) सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए अंतर-सरकारी वित्तीय संस्थानों और बहुराष्ट्रीय निगमों को विनियमित करने के लिए।



ब्रिटानिका से अधिक

नैतिकता: अधिकार सिद्धांत

बिरादरी : एकजुटता या समूह अधिकार

अंततः, एकजुटता या समूह के अधिकारों से बनी तीसरी पीढ़ी, अधिकारों की पहली दो पीढ़ियों से जुड़ी मांगों को आकर्षित और पुनः संकल्पित करते हुए, 20वीं सदी के मध्य से राज्य के उत्थान और पतन दोनों के उत्पाद के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझी जाती है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 28 में पूर्वाभास के अनुसार, जो घोषणा करता है कि "हर किसी को एक सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा में निर्धारित अधिकारों को पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है," यह पीढ़ी अब तक छह दावा किए गए अधिकारों को गले लगाती दिखाई देती है (हालांकि 21वीं सदी की शुरुआत की घटनाएँ यकीनन यह सुझाव देती हैं कि सातवां दावा किया गया अधिकार- लोकतंत्र का अधिकार- उभरने की प्रक्रिया में हो सकता है)। दावा किए गए अधिकारों में से तीन 1960 और 70 के दशक में विकासशील देशों में राष्ट्रवाद के उद्भव और "बढ़ती अपेक्षाओं की क्रांति" (यानी, शक्ति, धन और अन्य महत्वपूर्ण मूल्यों या क्षमताओं के वैश्विक पुनर्वितरण की मांग) को दर्शाते और "मानव जाति की साझी विरासत" (साझा पृथ्वी और अंतरिक्ष संसाधन; वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य जानकारी और प्रगति; और सांस्कृतिक परंपराएँ, स्थल और स्मारक) में भाग लेने और उससे लाभ उठाने का अधिकार। शेष तीन दावा किए गए एकजुटता या समूह अधिकार- शांति का अधिकार, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, और मानवीय आपदा राहत का अधिकार- कुछ महत्वपूर्ण मामलों में राज्य की नपुंसकता या अक्षमता का सुझाव देते हैं।

इन सभी घोषित अधिकारों को सामूहिक अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके लिए सभी सामाजिक ताकतों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता होती है, जो कि वैश्विक स्तर पर काफी हद तक आवश्यक है। हालांकि, उनमें से प्रत्येक एक व्यक्तिगत आयाम को भी प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, जबकि यह कहा जा सकता है कि सभी देशों और लोगों (विशेष रूप से विकासशील देशों और गैर-स्वशासित लोगों) का सामूहिक अधिकार है कि वे एक "नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था" हासिल करें जो उनके आर्थिक और सामाजिक विकास की बाधाओं को दूर करेगी, इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि यह प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है कि वह एक ऐसी विकास नीति से लाभान्वित हो जो भौतिक और अभौतिक मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि पर आधारित हो। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से अधिकांश एकजुटता अधिकार न्यायसंगत चरित्र के बजाय आकांक्षामय अधिक हैं और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के रूप में उनकी स्थिति कुछ अस्पष्ट बनी हुई है।

IV. निष्कर्ष

इस प्रकार, आधुनिक इतिहास के विभिन्न चरणों में, मानवाधिकारों की विषय-वस्तु को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, इस अपेक्षा के साथ नहीं कि एक पीढ़ी से जुड़े अधिकार दूसरी पीढ़ी के आरोहण के साथ पुराने हो जाएंगे या हो जाने चाहिए, बल्कि व्यापक रूप से या पूरक रूप से। मानवाधिकारों की विषय-वस्तु का इतिहास अलग-अलग समय पर और अलग-अलग दृष्टिकोणों से विकसित और परस्पर विरोधी धारणाओं को दर्शाता है, जिन मूल्यों या क्षमताओं पर सबसे अधिक जिम्मेदारी से ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ ही, निरंतरता और स्थिरता के लिए मानव जाति की आवर्ती मांगें भी। इस तरह की गतिशीलता, उदाहरण के लिए, एक बढ़ती हुई आम सहमति में परिलक्षित होती है कि मानवाधिकार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों तक फैले हुए हैं - यानी, गैर-राज्य और साथ ही राज्य अभिनेताओं को मानवाधिकारों के अपने उल्लंघन के लिए जवाबदेह होना चाहिए। इसी तरह मानवाधिकार विकास के लिए निरंतर दबाव को दर्शाते हुए एक मौजूदा सुझाव है कि मानवाधिकारों की एक "चौथी पीढ़ी" मौजूद है जिसमें महिलाओं और अंतर-पीढ़ी के अधिकार (यानी, मौजूदा बच्चों सहित भविष्य की पीढ़ियों के अधिकार) शामिल हैं। [30]

संदर्भ

1. जे. वाल्ड्रोन, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स: बेन्थम, बर्क एंड मार्क्स ऑन द राइट्स ऑफ मैन, मेथ्यू, लंदन, 1987 में इन तीन क्लासिक आलोचनाओं पर उत्कृष्ट चर्चाएं हैं।
2. बर्क, जे. वाल्ड्रोन, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स: बेन्थम, बर्क एंड मार्क्स ऑन द राइट्स ऑफ मैन, मेथ्यू, लंदन, 1987, पृष्ठ 99 में उद्धृत। ←□
3. बेन्थम, जे. वाल्ड्रोन, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स: बेन्थम, बर्क एंड मार्क्स ऑन द राइट्स ऑफ मैन, मेथ्यू, लंदन, 1987, पृष्ठ 53 में उद्धृत। ←□
4. मार्क्स का यहूदी प्रश्न पर लेख, जैसा कि जे. वाल्ड्रोन, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स: बेन्थम, बर्क एंड मार्क्स ऑन द राइट्स ऑफ मैन, मेथ्यू, लंदन, 1987, पृ. 137-150 में छपा है। ←□
5. ए. मैकइंटायर, आफ्टर वर्चु: ए स्टडी इन मोरल थ्योरी, डकवर्थ, लंदन, 1981, पृ. 67. ←□
6. जे. टैसियोलस, मानवाधिकारों की नैतिक वास्तविकता, टी. पोगे (संपादक), मानवाधिकार के रूप में गरीबी से मुक्ति। बहुत गरीबों का क्या ऋणी है?, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 2007, पृष्ठ 75. ←□
7. जे. रॉल्स, द लॉ ऑफ पीपल्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, 1999, पृ. 27. ←□
8. जिस अवधारणा को मैं यहां "रूढ़िवादी" के रूप में वर्णित कर रहा हूँ, वह तासियोलस द्वारा अपने लेखन में इस्तेमाल किए गए शब्द के अनुसार, कई अन्य तरीकों से भी परिभाषित की जाती है: "पारंपरिक दृष्टिकोण" (जे. रेज़, ह्यूमन राइट्स विदाउट फाउंडेशन, एस. बेसन और जे. तासियोलस (संपादकों), द फिलॉसफी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 2010, पृ. 323); "मानवतावादी अवधारणा" (पी. गिलाबर्ट, ह्यूमनिस्ट एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल थ्योरी, 39 (4), 2011 में); "प्राकृतिक-कानून दृष्टिकोण" (एल. वैलेंटिनी, इन व्हाट सेंस आर ह्यूमन राइट्स पॉलिटिकल? ए प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन "प्रकृतिवादी अवधारणा" (एम. लियाओ-ए. इटिसन, मानवाधिकारों की राजनीतिक और प्रकृतिवादी अवधारणाएँ: एक गलत विवाद?, जर्नल ऑफ मोरल फिलॉसफी में, संख्या 9, 2012); "मानव वाहक दृष्टिकोण" (जे. वाल्ड्रोन, मानवाधिकार: रेज़/रॉल्स दृष्टिकोण की आलोचना, ए. इटिसन (संपादक), मानवाधिकार: नैतिक या राजनीतिक?, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 2018, पृष्ठ 117)। ←□
9. जे. रॉल्स, द लॉ ऑफ पीपल्स, पृष्ठ 3. ←□
10. "सार्वजनिक कारण" की अवधारणा के लिए देखें जे. रॉल्स, द लॉ ऑफ पीपल्स, पृ. 129-180; पीपल्स लॉ के संबंध में सार्वजनिक कारण के विचार के लिए देखें इबिडेम, पृ. 121-123.
11. मैं लोगों के बारे में रॉल्स की धारणा को समझने का तरीका छोड़ देता हूँ। ←□
12. रॉल्स की मानवाधिकार सूची में शामिल हैं: जीवन का अधिकार (जीविका और सुरक्षा के साधनों का); स्वतंत्रता का अधिकार (दासता, दासता और जबरन कब्जे से मुक्ति का अधिकार, और धर्म और विचार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विवेक की पर्याप्त स्वतंत्रता का अधिकार); संपत्ति का अधिकार (व्यक्तिगत संपत्ति); और प्राकृतिक न्याय के नियमों द्वारा व्यक्त औपचारिक समानता का अधिकार (अर्थात्, समान मामलों को समान रूप से माना जाना चाहिए)। मानवाधिकारों को, जैसा कि इस प्रकार समझा जाता है, पश्चिमी परंपरा के लिए विशेष रूप से उदार या विशेष के रूप में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। वे राजनीतिक रूप से संकीर्ण नहीं हैं। जे. रॉल्स, द लॉ ऑफ पीपल्स, पृष्ठ 65 देखें।
13. वही, 81. ←□
14. वही, 27. ←□
15. वही, 78-79. ←□
16. वही, 79. ←□



17. वही , 80. ←□
18. के. बेन्स, टुवर्ड्स ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स , फिलॉसफी एंड सोशल क्रिटिसिज्म में , खंड 35, संख्या 4, 2009, पृ. 379. ←□
19. संक्षेप में: सरकार की आंतरिक स्वायत्तता की सीमाएँ निर्धारित करना और युद्ध के कारणों और उसके आचरण को प्रतिबंधित करना, अर्थात् केवल आत्मरक्षा में युद्ध करना, या अन्य लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करना जब उनकी अपनी या किसी अन्य सरकार द्वारा उनका उल्लंघन किया जाता है, और दुश्मन गैर-लड़ाकों के मानवाधिकारों का सम्मान करना। गैर-लड़ाकों के संबंध में, उन्हें हमले के लिए लक्षित नहीं किया जाना चाहिए, और उन्हें और उनकी संपत्ति को चोट से बचाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। ←□
20. एस. फ्रीमैन, परिचय: जॉन रॉल्स - एक अवलोकन , एस. फ्रीमैन (सं.), द कैम्ब्रिज कम्पेनियन टू रॉल्स , कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, यूके, 2003, पृ. 47. ←□
21. जे. रॉल्स, द लॉ ऑफ पीपल्स , पृष्ठ. 79. ←□
22. जैसा कि वे लिखते हैं, "लोगों का कानून अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दुनिया से आगे बढ़ता है जैसा कि हम इसे देखते हैं, और यह चिंता करता है कि एक उचित उदार लोगों की विदेश नीति क्या होनी चाहिए" (जे. रॉल्स, पीपुल्स का कानून , पृष्ठ 83. इबिडेम पृष्ठ 3; पृष्ठ 41; पृष्ठ 57 भी देखें)।
23. जे. रॉल्स, द लॉ ऑफ पीपल्स , पृ. 13; पृ. 65, और बी. विल्किंस, रॉल्स ऑन ह्यूमन राइट्स: ए रिव्यू एसे , द जर्नल ऑफ एथिक्स में , खंड 12, (1), 2008, पृ. 110-111. ←□
24. जे. रॉल्स, द लॉ ऑफ पीपल्स , पृष्ठ. 48. ←□
25. जे. रज़, ह्यूमन राइट्स विदाउट फाउंडेशन्स , पृष्ठ. 327. ←□
26. सी. बेइटज़, द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स , ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफ़ोर्ड, 2009, पृ. 103. ←□
27. जे. रज़, ह्यूमन राइट्स विदाउट फाउंडेशन्स , पृष्ठ. 328. ←□
28. इस विचार पर एक रोचक चर्चा, तथा राजनीतिक पहलुओं पर नैतिक पहलुओं की प्राथमिकता, एम. रेन्ज़ो, मानवाधिकार और नैतिकता की प्राथमिकता , सोशल फिलॉसफी एंड पॉलिसी , वॉल्यूम 32, 1, 2015 में है। इसके अलावा, रेन्ज़ो के दृष्टिकोण को ए. सांगियोवन्नी, न्याय और नैतिकता के लिए राजनीति की प्राथमिकता , जर्नल ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी , 16 (2), 2008 के लिए एक आदर्श विलंबित उत्तर के रूप में देखा जा सकता है ।
29. सी. बेइटज़, द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स, पृ. 39-42. ←□
30. जे. टैसियोलस, क्या मानवाधिकार अनिवार्य रूप से हस्तक्षेप के लिए प्रेरित करते हैं?, फिलॉसफी कम्पास में , 4, 6, 2009. ←□



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

| Mobile No: +91-6381907438 | Whatsapp: +91-6381907438 | ijmrset@gmail.com |

www.ijmrset.com